

अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन

यह अध्याय 2024-25 के लिए झारखण्ड के वित्त का एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की वित्तीय संरचना शामिल है। यह राजस्व और व्यय, ऋण स्तर और राजकोषीय घाटे में रुझानों का विश्लेषण, लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को उजागर करता है। यह अध्याय कम नकदी शेष, निवेश पर कम प्रतिफल आदि जैसे मुद्दों को भी चिह्नित करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड, पूर्वी भारत का मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जो 79,716 वर्ग कि. मी. में फैला हुआ है और इसमें 24 जिले और 32,394 गाँव शामिल हैं। जनसंख्या अनुमान (2011-2036) पर तकनीकी समूह के प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान राज्य की जनसंख्या 4.05 करोड़ (भारत की जनसंख्या का 2.87 प्रतिशत) होने का अनुमान है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 508 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यह खंड राज्य की जनसांख्यिकी, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय का अवलोकन प्रदान करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य के जनसांख्यिकीय विवरण नीचे तालिका 1.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

	झारखण्ड	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)	73.48	64.30
शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)	26.52	35.70
जनसंख्या घनत्व (जनसंख्या अनुमान 2011-36, एमओएचएफडब्ल्यू)	508	430
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात (भारत की जनगणना, 2011)	948	947
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर (नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020)	29	25
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर (मातृ मृत्यु बुलेटिन)	4	5
कुल प्रजनन दर (प्रतिशत) (जनसंख्या अनुमान 2011-36, एमओएचएफडब्ल्यू)	2.17	1.94
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष) (तकनीकी जनसंख्या पर रिपोर्ट, 2020)	69.5	70.3
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (प्रतिशत) (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)	28.81	14.96
साक्षरता दर (प्रतिशत) (एनसीएस रिपोर्ट, 2012-18)	76.7	80.9

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जैसा कि आगे की कड़िकाओं में चर्चा की गई है। आधार वर्ष 2011-12 के साथ वर्तमान श्रृंखला के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए जीएसडीपी के आंकड़े बदल गए हैं। तदनुसार, पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित प्रासंगिक वर्षों के लिए प्रासंगिक तालिकाओं में प्रतिशत/अनुपात में परिवर्तन हुआ है।

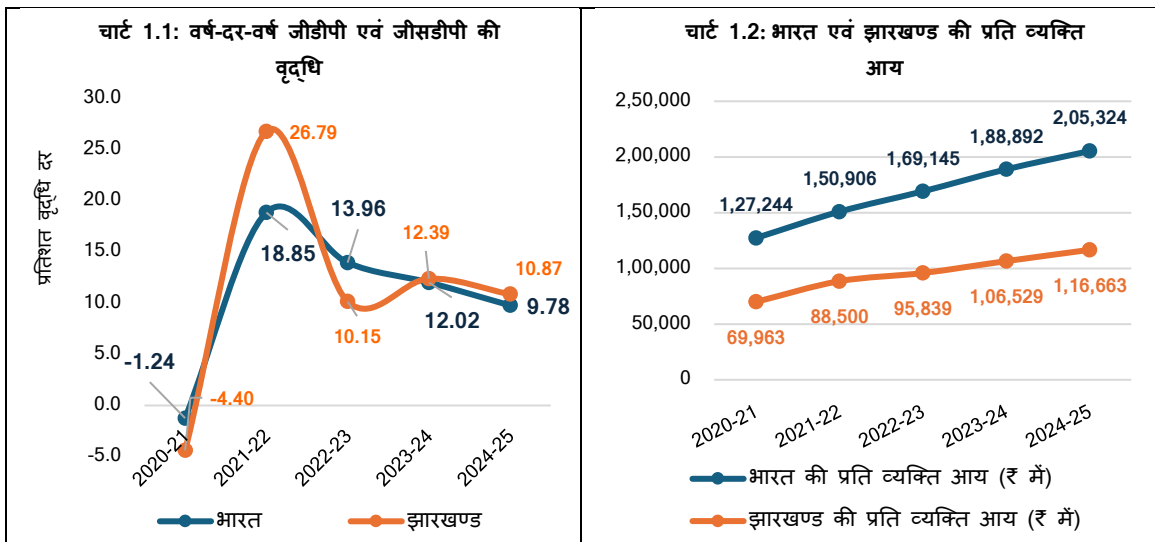
1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तात्पर्य एक देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, जबकि जीएसडीपी केंद्र के समान राज्य स्तर पर है, और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.2 में दी गई हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जीडीपी में जीएसडीपी का योगदान चार्ट 1.1 में दिया गया है। देश और राज्य की प्रति व्यक्ति आय (प्र.व्य.आ.) को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: भारत के जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर) की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
जीडीपी (₹ करोड़ में)	1,98,54,096	2,35,97,399	2,68,90,473	3,01,22,956	3,30,68,145
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	2,96,664	3,76,127	4,14,308	4,65,638	5,16,255
प्रति व्यक्ति आय- अखिल भारत (₹ में)	1,27,244	1,50,906	1,69,145	1,88,892	2,05,324
प्रति व्यक्ति आय (झारखण्ड) (₹ में)	69,963	88,500	95,839	1,06,529	1,16,663

स्रोत: एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार



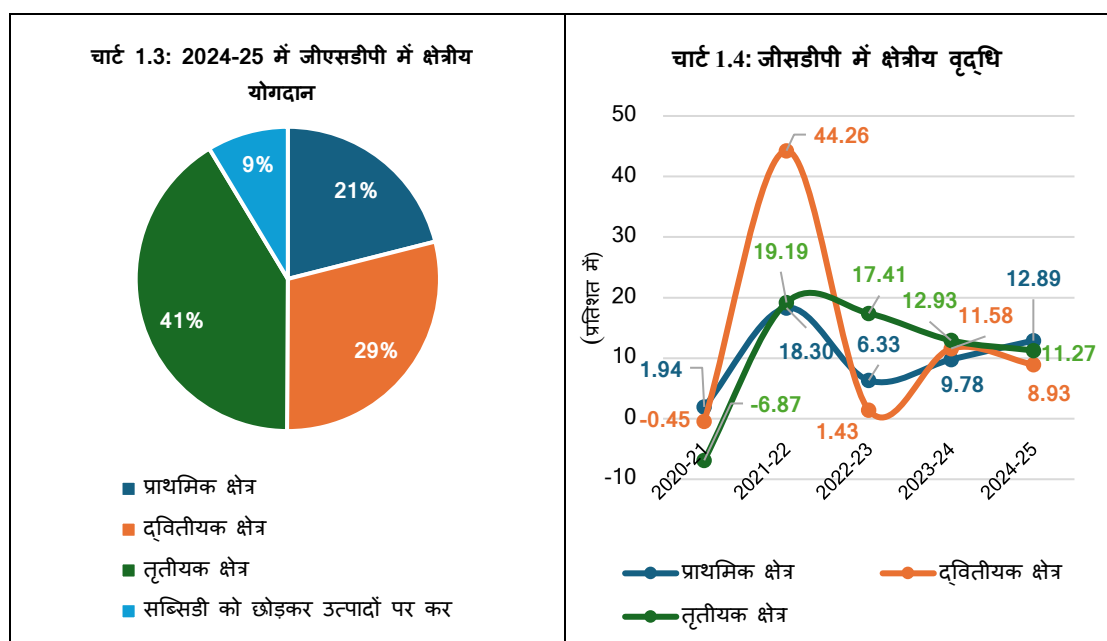
पिछले पांच वर्षों में झारखण्ड की जीएसडीपी की वृद्धि (74 प्रतिशत) भारत की जीडीपी की वृद्धि (67 प्रतिशत) से अधिक थी। हालांकि, 2020-25 के दौरान भारत के जीडीपी में झारखण्ड का योगदान 1.5 प्रतिशत पर लगभग समान रहा। 2020-21 और 2022-23

को छोड़कर, 2020-25 के दौरान भारत के जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि अधिक थी।

2020-25 की अवधि के दौरान झारखण्ड का प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय का 55 से 59 प्रतिशत के बीच था।

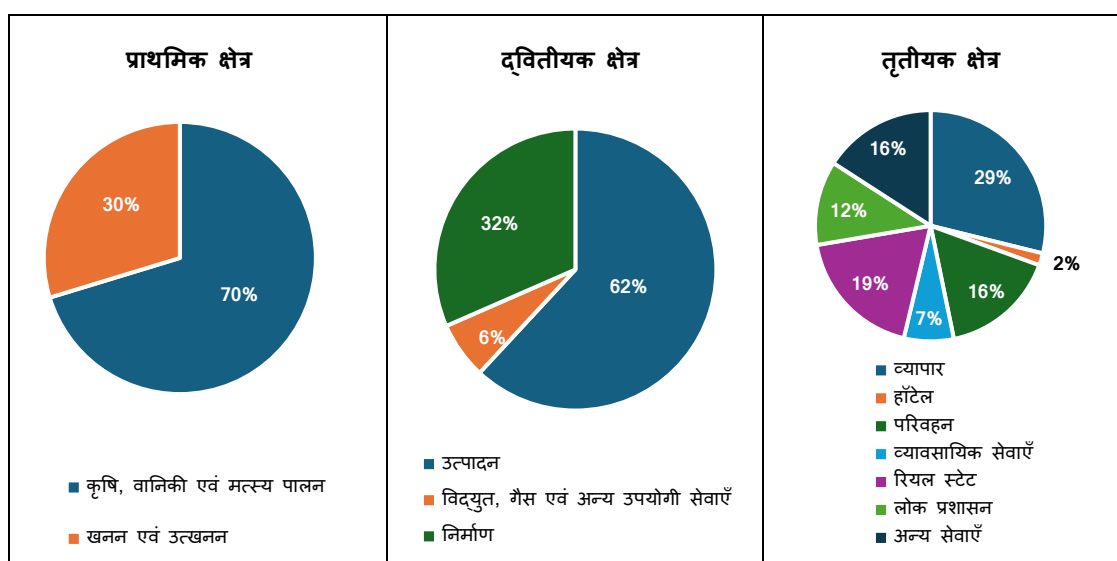
1.1.2.2 जीएसडीपी में क्षेत्र-वार योगदान

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का क्षेत्र-वार योगदान और पिछले पांच वर्षों के दौरान जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः चार्ट 1.3 और चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।



चार्ट 1.5 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र के अवयवों को उसके प्रमुख योगदान करने वाले खंडों के संदर्भ में दर्शाता है।

चार्ट 1.5: क्षेत्र-वार वितरण, वित्तीय वर्ष 2024-25



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

पिछले पांच वर्षों के दौरान तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान बना रहा, जबकि द्वितीयक क्षेत्र ने महामारी के बाद सुधार दिखाई और प्राथमिक क्षेत्र ने अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सेदारी बनाए रखी।

1.1.3 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 में वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (ब. अ.), संशोधित अनुमान (सं. अ.) और जीएसडीपी से वास्तविक के प्रतिशत के साथ-साथ वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए राज्य के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिखाया गया है।

तालिका 1.3: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)	ब.अ. के साथ वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	कर राजस्व	65,357.12	74,538.22	76,385.28	71,058.60	95.33	13.76
(i)	स्व-कर राजस्व	28,004.77	34,196.67	32,827.00	28,501.30	83.35	5.52
(ii)	संघ के करों / शुल्कों का हिस्सा	37,352.35	40,341.55	43,558.28	42,557.30	105.49	8.24
2	गैर-कर राजस्व	13,425.12	19,300.43	20,026.54	14,231.39	73.74	2.76
3	केंद्र सरकार से सहायता-अनुदान	9,146.26	16,961.35	13,925.93	9,198.62	54.23	1.78
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	87,928.50	1,10,800.00	1,10,337.75	94,488.61	85.28	18.30
5.	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	7,276.70	100	380.61	196.69	196.69	0.04
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	उधार और अन्य देनदारियाँ	6,331.76	9,499.68	11,482.69	14,526.81	152.92	2.81
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	13,608.46	9,599.68	11,863.30	14,723.50	153.37	2.85
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,01,536.96	1,20,399.68	1,22,201.05	1,09,212.11	90.71	21.15
10	राजस्व व्यय	76,676.42	91,831.54	98,474.22	86,565.04	94.27	16.77
11	ब्याज भुगतान	6,838.95	7,054.57	7,152.38	5,863.01	83.11	1.14
12	पूँजीगत व्यय	20,569.69	23,987.25	19,095.94	18,409.98	76.75	3.57
13	ऋण और अग्रिम	4,290.85	4,580.89	4,630.89	4,237.10	92.50	0.82
14	कुल व्यय (10+12+13)	1,01,536.96	1,20,399.68	1,22,201.05	1,09,212.12	90.71	21.15
15	राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (4-10)	11,252.08	18,968.46	11,863.53	7,923.57	41.77	1.53
16	राजकोषीय अधिशेष (+)/ घाटा (-) {(4+5+6)-14}	-6,331.76	-9,499.68	-11,482.69	-14,526.82	152.92	-2.81
17	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (16-11)	507.19	-2,445.11	-4,330.31	-8,663.81	354.33	-1.68

स्रोत: राज्य के वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण

*उधार और अन्य देनदारियाँ: लोक ऋण की निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे की निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) + नकद शेष की आरंभिक तथा अंत शेष का निवल।

जैसा कि तालिका 1.3 से देखा जा सकता है, 2024-25 के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। हालांकि, पिछले वर्षों से राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष में काफी कमी आई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है।

1.1.4 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का दस वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण

राज्य के प्रमुख राजकोषीय और आर्थिक मापदंडों के 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान एक व्यापक दस वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण किया गया है (परिशिष्ट 1.2 में प्रस्तुत) ताकि राज्य को राजकोषीय स्थिरता पर एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। विश्लेषण में दस वर्ष की अवधि में प्रत्येक घटक के लिए सीएजीआर की गणना शामिल है। यह राज्य के वित्त की संरचनात्मक सामर्थ्य और कमियों का आकलन करने में सक्षम बनाता है, उभरते जोखिमों की पहचान करता है और व्यवस्थित रूझानों को उजागर करता है जिन्होंने दशक के दौरान राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किया है।

➤ राजस्व प्राप्तियाँ

पिछले दस वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें लगभग 9.83 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से उच्च स्व-कर राजस्व और संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण थी। इस दस वर्ष की अवधि में, राजस्व व्यय में वृद्धि को बनाये रखने के लिए राजस्व वृद्धि की गति पर्याप्त थी, जिसके कारण 2020-21 को छोड़कर, 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष रहा। इस अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष 7.64 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ बढ़ा।

• स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व में 10.63 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई। यह वृद्धि एसजीएसटी संग्रह में सुधार और राज्य आबकारी, वाहनों पर कर आदि से अधिक संग्रह के कारण हुआ।

• गैर-कर राजस्व

इस अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व में 10.38 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई। वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता मुख्य रूप से विविध सामान्य सेवाओं, उपयोगकर्ता शुल्क आदि के तहत राजस्व संग्रह और ब्याज प्राप्तियों में भिन्नता के कारण थी।

• संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी

संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी लगभग 11.51 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी। महामारी के वर्षों के दौरान गिरावट को छोड़कर, इसने 2015-16 और 2024-25 के बीच लगातार वृद्धि को दिखाया है। यह घटक राज्य की राजकोषीय स्थिरता में प्राथमिक भूमिका निभाता है।

- **भारत सरकार से सहायता-अनुदान**

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान में कमी के कारण, दस साल की अवधि के उत्तरार्ध में विशेष रूप से 2023-24 और 2024-25 में भारत सरकार से सहायता-अनुदान में भारी गिरावट आई।

- **राजस्व व्यय**

राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई, जो लगभग 10.05 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ी। हालांकि, 2020-21 को छोड़कर पूरे दशक में राज्य का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से कम था, जो राजकोषीय स्थिरता को दर्शाता है। 2015-16 और 2024-25 के बीच की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 36.65 प्रतिशत और 45.42 प्रतिशत के बीच रहा।

- **ब्याज भुगतान**

लोक ऋण में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि हुई, और लगभग 6.52 प्रतिशत की सीएजीआर पर वृद्धि हुई। इस प्रकार ब्याज भुगतान 2015-16 और 2024-25 के बीच की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 6.20 प्रतिशत और 10.31 प्रतिशत के बीच था।

- **सब्सिडी**

2015-16 और 2024-25 के बीच की अवधि में सब्सिडी में लगभग 35.22 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई, जिसमें महामारी के दौरान और उसके बाद तेजी से वृद्धि हुई, जो विस्तारित कल्याणकारी व्यय को दर्शाती है। बढ़ते सब्सिडी बोझ के लिए समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा व्यय लक्षित बना रहे और राज्य के वित्त पर दबाव न डाले।

- **पूँजीगत प्राप्तियाँ**

2015-16 और 2024-25 के बीच पूँजीगत प्राप्तियों में लगभग (-) 3.81 प्रतिशत की सीएजीआर से कमी आई है। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे कि ऋणों और अग्रिमों की वसूली, 2023-24 को छोड़कर अल्प रही।

- **पूँजीगत व्यय**

पूँजीगत व्यय में लगभग 9.46 प्रतिशत की सीएजीआर की वृद्धि हुई, जो परिसंपत्ति निर्माण पर बल देता है। पूँजीगत व्यय 2023-24 में सबसे अधिक था और 2024-25 के दौरान थोड़ा कम हो गया।

- **राजकोषीय घाटा**

राजकोषीय घाटा (रा. घा.) लगभग 2.61 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। हालाँकि, 2020-21 को छोड़कर, 2015-16 और 2024-25 के बीच की अवधि के दौरान, यह संबंधित वर्षों के एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्यों के नीचे रहा।

➤ प्राथमिक घाटा

राज्य के पास 2021-22 से 2023-24 के दौरान प्राथमिक अधिशेष था, जबकि शेष वित्तीय वर्षों (2015-16 और 2024-25 के बीच) में राज्य के पास प्राथमिक घाटा था। पिछले दस वर्षों में प्राथमिक घाटा 0.61 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा।

➤ बकाया देनदारियां

पिछले दशक में बकाया देनदारियां दोगुनी से अधिक हो गईं, जो 2015-16 से 2024-25 के दौरान 9.67 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रही हैं। 2017-21 की अवधि को छोड़कर, एमटीएफपीएस में ऋण-जीएसडीपी अनुपात निर्धारित सीमा से नीचे रहा।

दस साल का वित्तीय रुझान दर्शाता है कि:

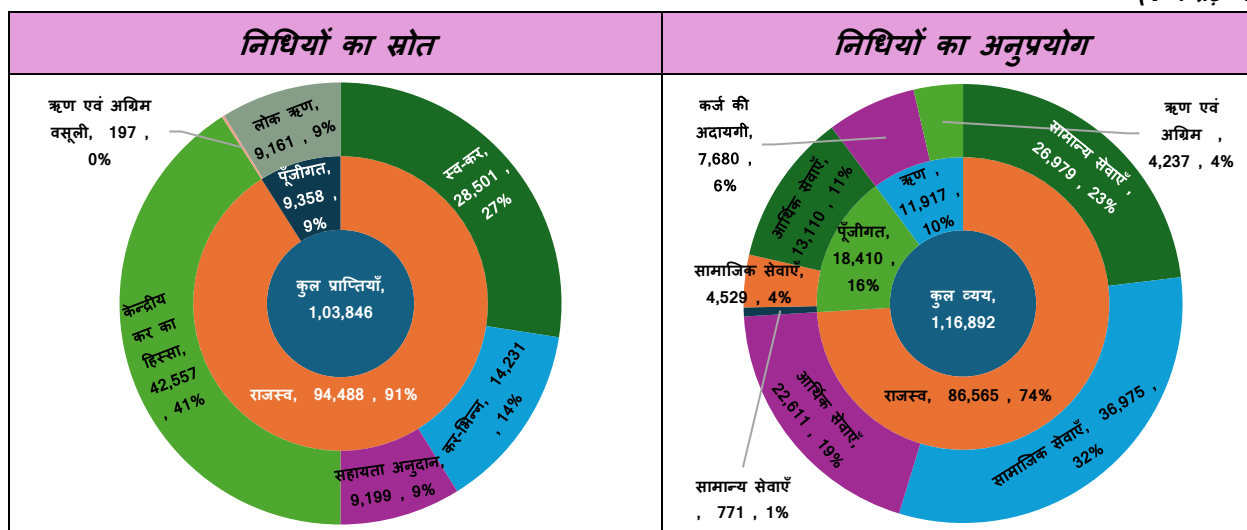
- राजस्व व्यय में वृद्धि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक थी, जिससे राजस्व असंतुलन हो सकता है।
- बढ़ती सब्सिडी और प्रतिबद्ध व्यय ने विकास योजनाओं पर व्यय के लिए जगह कम कर दी।
- बढ़े हुए पूँजीगत व्यय ने दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण और आर्थिक विकास को दर्शाया।

1.1.5 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के स्रोतों और निधियों के अनुप्रयोग के घटकों की तुलना चार्ट 1.6 में दी गई है।

चार्ट 1.6: 2024-25 के दौरान निधि के स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेख

परिशिष्ट 1.3 में वर्तमान वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष के दौरान प्राप्तियों और संवितरणों और राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति का विवरण दिया गया है।

1.1.6 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। **परिशिष्ट 1.4** में ऐसी देयताओं और संपत्तियों का सार दिया गया है, जो 31 मार्च 2025 को विगत वर्ष की संबंधित स्थिति से तुलना है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखा और रक्षित निधि से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की एक संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्ति				
		2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि / कमी		2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि / कमी	
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	70,658.82	69,595.32	-1.51	क	सकल पूँजीगत व्यय	1,39,979.87	1,58,389.84	13.15
ख.	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम*	16,148.68	15,574.66	-3.55	ख.	ऋण और अग्रिम	25,527.35	29,567.76	15.83
आकस्मिकता निधि		500	500	0					
लोक लेखा									
क	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1,557.43	2,238.21	43.71	क	विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम	0	4.22	100
ख.	जमा	30,847.92	31,560.28	2.31	ख.	प्रेषण	0	0	0
ग	रक्षित निधि	10,666.62	14,725.39	38.05	ग	उचंत और विविध	0	0	0
घ	प्रेषण	48.08	224.38	366.68		नकद शेष (कर्णांकित निधियों में निवेश सहित)	10,735.61	3,295.67	-69.30
च	उचंत और विविध	380.83	362.72	-4.76		उचंत और विविध	0.00	0.00	0.00
	व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता	45,434.45	56,476.53	24.30		प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता	0.00	0.00	0.00
कुल		1,76,242.83	1,91,257.49	8.52	कुल		1,76,242.83	1,91,257.49	8.52

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* खातों में प्रोफार्मा सुधार करके 2024-25 की आरंभिक शेष राशि में ₹ 3,118.51 करोड़ (बैंक-टू-बैंक ऋण) की कमी की गई है।

1.2 राज्य की समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन राज्य के समेकित निधि का हिस्सा हैं।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

पांच वर्ष की अवधि (2020-25) में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि तालिका 1.5 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्ति

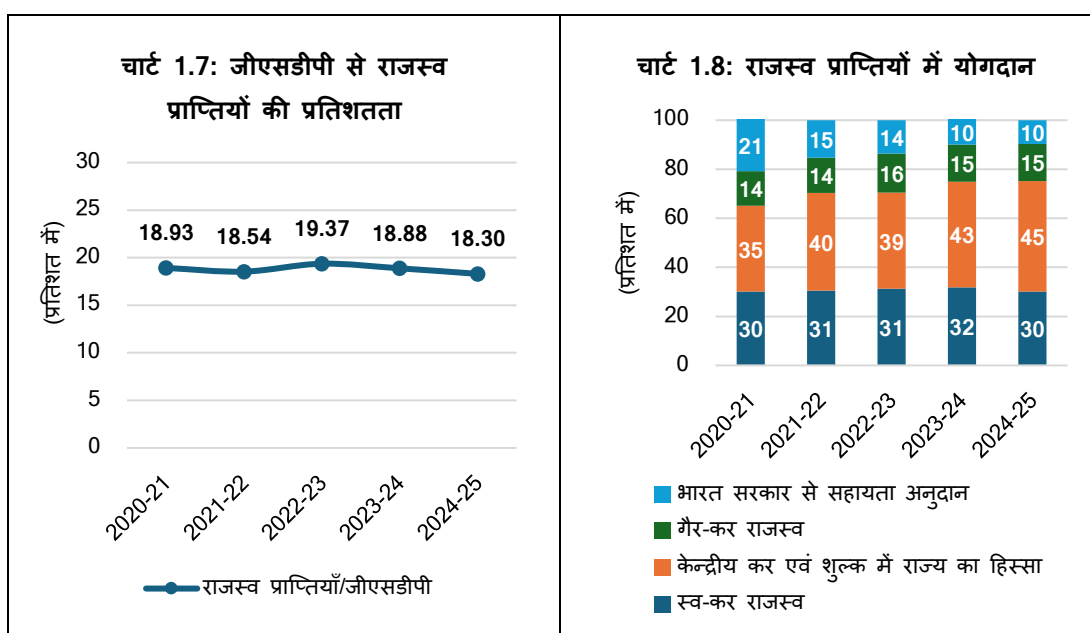
(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियाँ	56,150	69,722	80,245	87,929	94,489
कर राजस्व	36,592	49,025	56,522	65,357	71,058
स्व-कर राजस्व	16,880	21,290	25,118	28,005	28,501
संघ के करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी	19,712	27,735	31,404	37,352	42,557
गैर-कर राजस्व	7,564	10,031	12,830	13,425	14,231
भारत सरकार से सहायता-अनुदान	11,993	10,667	10,894	9,146	9,199
राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर और गैर-कर राजस्व)	24,444	31,321	37,948	41,430	42,732
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	2,96,664	3,76,127	4,14,308	4,65,638	5,16,255
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियाँ	-3.88	24.17	15.09	9.58	7.46
राज्य का स्व-राजस्व	-4.22	28.13	21.16	9.18	3.14
राज्य का स्व-कर राजस्व	0.65	26.12	17.98	11.50	1.77
जीएसडीपी	-4.4	26.79	10.15	12.39	10.87
उत्प्लावकता अनुपात					
जीएसडीपी के मुकाबले राज्य के स्व-कर राजस्व में वृद्धि	*	0.97	1.77	0.93	0.16

स्रोत: जीएसडीपी आंकड़ों के लिए एमओएसपीआई और राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेख

* उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि जीएसडीपी वृद्धि नकारात्मक थी।

राजस्व प्राप्तियों का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों का योगदान चार्ट 1.7 और चार्ट 1.8 में दिया गया है।

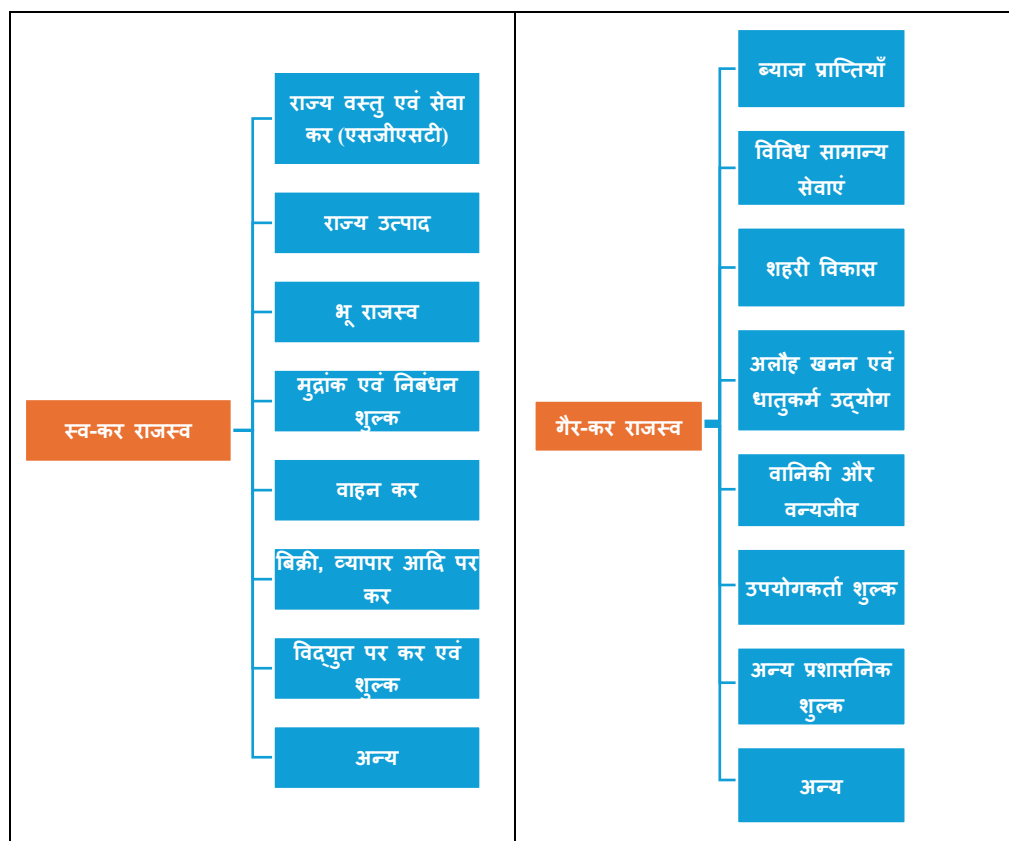


जैसा कि तालिका 1.5 से देखा जा सकता है, चालू वर्ष में जीएसडीपी के लिए राज्य के स्व-कर राजस्व की उत्प्लावकता में कमी आई है। यह जीएसडीपी की तुलना में

स्व-कर राजस्व की कम वृद्धि के कारण है। इसके अलावा, जैसा कि चार्ट 1.7 से देखा जा सकता है, राजस्व प्राप्तियों से जीएसडीपी अनुपात में 2022-23 से कमी की प्रवृत्ति दिखाई गई। राजस्व प्राप्तियों में संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से का योगदान पिछले दो वर्षों में बढ़ा है, जैसा कि चार्ट 1.8 में देखा जा सकता है।

क. राज्य के अपने संसाधन

चार्ट 1.9: राज्य के स्व-राजस्व का विवरण



(i) स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व वह राजस्व है जो राज्य सरकार द्वारा संविधान के तहत लगाए जाने वाले करों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक, बजट अनुमान (ब.अ.), पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.), और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्व-कर राजस्व के वास्तविक तालिका 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: स्व-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25
(बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान, और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

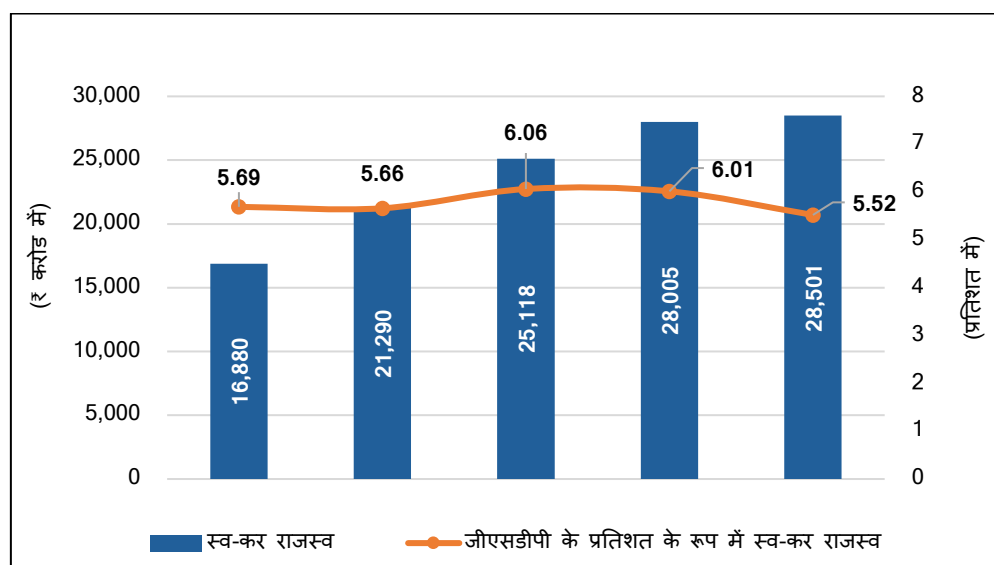
कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
राज्य उत्पाद एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	12,348	15,375	15,000	13,980
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,949	9,121	9,000	6,686
राज्य उत्पाद शुल्क	2,376	2,700	2,800	2,708
विद्युत पर कर और शुल्क	1,395	1,413	1,450	1,367
भू राजस्व	1,666	1,700	1,700	543
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	1,468	1,450	1,500	1,258
वाहनों पर कर	1,756	2,350	2,290	1,912
अन्य	47	88	87	47
कुल	28,005	34,197	33,827	28,501

स्रोत: राज्य के वित्त लेख और बजट दस्तावेज

जैसा कि तालिका 1.6 से देखा जा सकता है, राज्य के स्व-कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान मामूली वृद्धि हुई है।

2020-21 से 2024-25 के दौरान स्व-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः चार्ट 1.10 और चार्ट 1.11 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.10: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेख

चार्ट 1.11: राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 1.11 से देखा जा सकता है, राज्य के स्व-कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि, एसजीएसटी और भू-राजस्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में ₹ 1,632 करोड़ की वृद्धि हुई। इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन और 'एसजीएसटी के कर घटक के हस्तांतरण में आईजीएसटी हस्तांतरण का विभाजन' के कारण हुआ।
- 2024-25 के दौरान भू-राजस्व संग्रह ₹ 1,123 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ 543 करोड़ रह गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चतर प्राप्तिyaँ पट्टे पर सरकारी भूमि के हस्तांतरण के कारण थीं।

(ii) गैर-कर राजस्व

राज्य का गैर-कर राजस्व राज्य सरकार की करों के अलावा अन्य स्रोतों जैसे किराया, शुल्क, रॉयल्टी और अन्य प्राप्तिyaँ से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गैर-कर राजस्व के वास्तविक, बजट अनुमान (ब. अ.), संशोधित अनुमान (सं. अ.), और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक, तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: गैर-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बजट अनुमान, राजस्व व्यय, और वास्तविक)

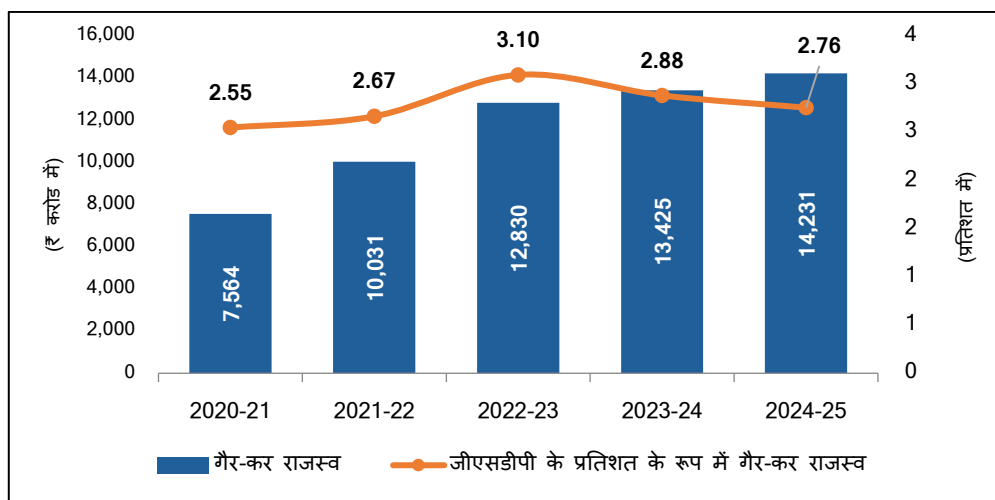
(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
गैर-लोह अयस्क खनन और धातुकर्म उद्योग	10,597	15,500	17,642	12,086
वानिकी और वन्य जीवन	816	900	100	926
ब्याज प्राप्तिyaँ	431	380	572	137
उपयोगकर्ता प्रभार*	283	347	464	386
शहरी विकास	138	267	175	165
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	186	210	200	49
विविध सामान्य सेवाएं	413	946	295	4.
अन्य	561	750	579	578
कुल	13,425	19,300	20,027	14,231

*शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सिंचाई, परिवहन और पर्यटन से संबंधित सभी गैर-कर राजस्व, जिसका प्रमुख शीर्ष 0202, 0210, 0700, 0701, 1054 और 1452 से संबंधित हैं, उपयोगकर्ता शुल्क हैं।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तिyaँ क्रमशः चार्ट 1.12 और चार्ट 1.13 में दिखाई गई हैं।

चार्ट 1.12: गैर-कर राजस्व में रुझान

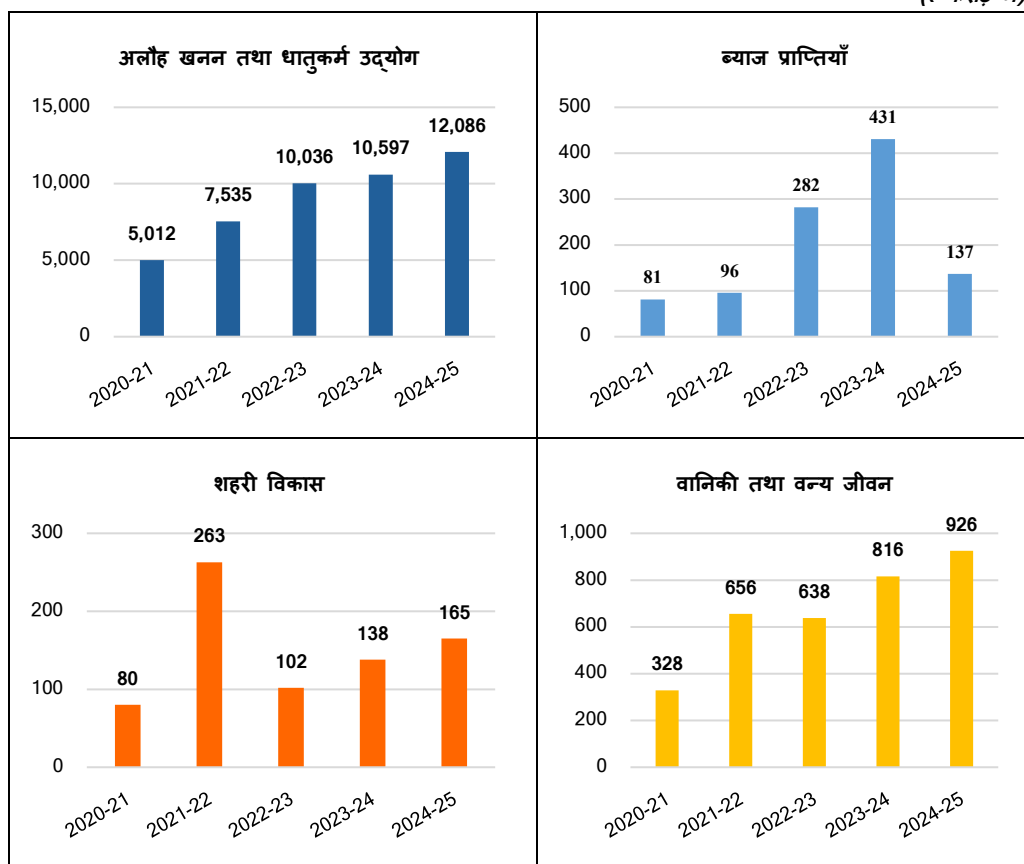


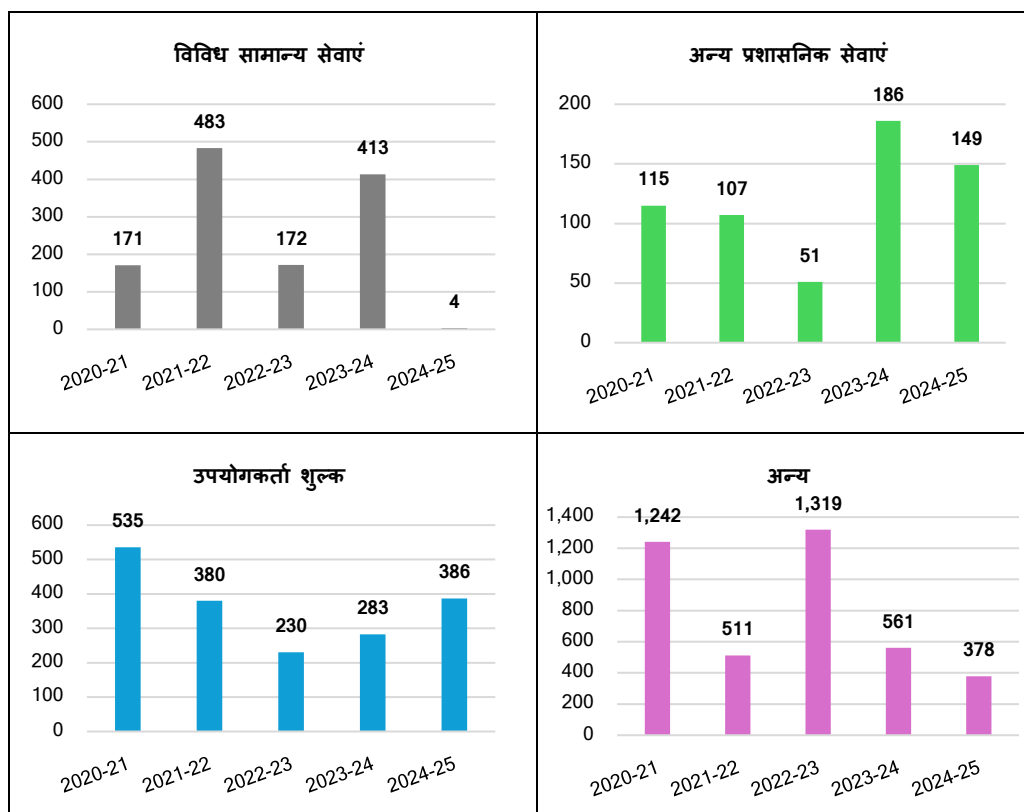
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत राजस्व संग्रह में वृद्धि के कारण 2024-25 में गैर-कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आंशिक रूप से विविध सामान्य सेवाओं, ब्याज प्राप्तियों और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के तहत कम संग्रह से प्रतिपूरित हुई।

चार्ट 1.13: राज्य के गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)





स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यद्यपि अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथापि राज्य के अनुमान की तुलना में इसका संग्रह बहुत कम रहा है। ब्याज प्राप्तियों और विविध सामान्य सेवाओं का संग्रह भी बजट अनुमानों से काफी कम था।

ख. संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा

संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के घटकों का रुझान तालिका 1.8 में दिखाए गए हैं।

तालिका 1.8: संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी

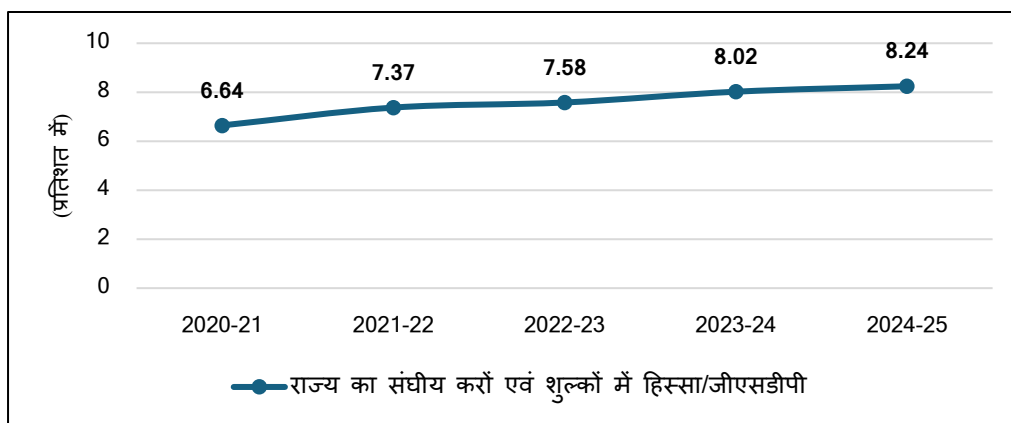
(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	5,863	8,367	8,874	11,336	12,429
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी)	0	0	0	0	0
निगम कर	5,944	7,139	10,529	11,212	12,076
निगम कर के अलावा आय पर कर	6,093	8,693	10,279	12,948	15,400
सीमा शुल्क	1,050	2,060	1,235	1,309	2,165
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	663	1,089	387	495	417
सेवा कर	85	356	49	7	1
अन्य कर	14	31	51	45	69
कुल	19,712	27,735	31,404	37,352	42,557

स्रोत: वित्त लेखे

जीएसडीपी से केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से का प्रतिशत चार्ट 1.14 में दिया गया है।

चार्ट 1.14: जीएसडीपी के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के कुल हिस्से का प्रतिशत



2020-21 से 2024-25 के दौरान संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी।

वर्ष के दौरान संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 19 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में केवल 14 प्रतिशत थी। हालांकि, जीएसडीपी में इसका प्रतिशत 2023-24 में 8.02 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 8.24 प्रतिशत हो गया, जैसा कि चार्ट 1.14 में देखा जा सकता है।

ग. भारत सरकार से सहायता-अनुदान

भारत सरकार से सहायता-अनुदान और उसके घटकों की प्रवृत्ति तालिका 1.9 में दिखाई गई है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायता-अनुदान

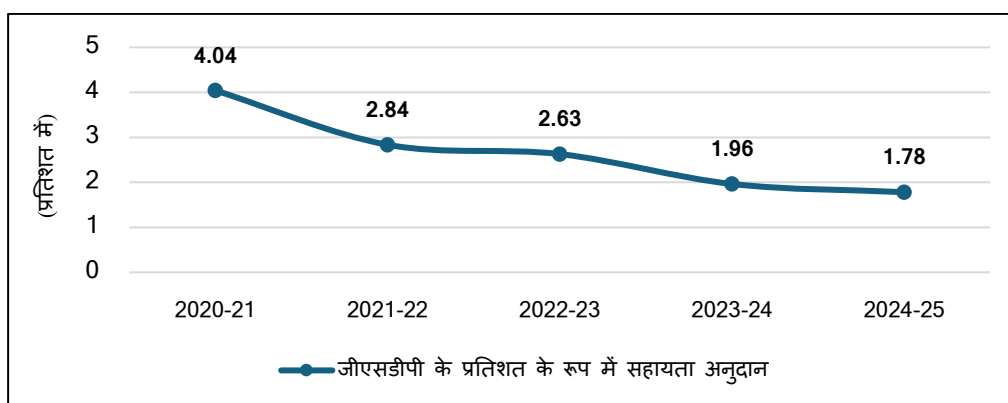
(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	(-) 63.36	0.00
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	6,838.85	6,577.16	6,871.79	6,330.07	6,714.04
वित्त आयोग अनुदान	2,990.50	2,198.30	1,826.59	2,378.28	2,144.92
विधायिका वाले राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण / अनुदान	2,164.06	1,891.40	2,195.16	501.27	339.65
कुल	11,993.41	10,666.86	10,893.54	9,146.26	9,198.61

स्रोत: वित्त लेखे

जीएसडीपी से भारत सरकार से सहायता-अनुदान का प्रतिशत चार्ट 1.15 में दिया गया है।

चार्ट 1.15: जीएसडीपी से भारत सरकार से सहायता-अनुदान का प्रतिशत



भारत सरकार से सहायता-अनुदान 2020-21 में ₹ 11,993.41 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 9,198.61 करोड़ हो गई, जो वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान के लिए राज्य को मुआवजे की समाप्ति के कारण हुई थी। हालांकि, 2023-24 और 2024-25 के दौरान सहायता-अनुदान लगभग समान रहा।

(i) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹ 6,714.04 करोड़ के अनुदान में से, तालिका 1.10 में दर्शाई गई योजनाओं के लिए राज्य के बजट में प्रमुख आवंटन किए गए थे।

तालिका 1.10: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

योजना का नाम	2023-24 राशि (₹ करोड़ में)	2024-25 राशि (₹ करोड़ में)	पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन की प्रतिशतता
सर्व शिक्षा अभियान के तहत समग्र शिक्षा	1,354.00	1,234.00	-8.86
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	181.73	82.27	-54.73
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)	162.08	98.35	-39.32
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों और पुलों का निर्माण	231.46	971.77	319.84
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	12.00	658.22	5385.17
इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना	227.73	259.19	13.81

स्रोत: वित्त लेख

जैसा कि देखा जा सकता है, 2023-24 और 2024-25 के बीच राज्य को प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए किए गए आवंटन में महत्वपूर्ण भिन्नता थी (समग्र शिक्षा अभियान के मामले को छोड़कर)। हालाँकि, इन अंतरों के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

(ii) पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान स्थानीय निकायों, राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ), राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) और स्थानीय निकायों (एलबी) के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्यों को प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी तथा सहायता-अनुदान का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश	2024-25 के दौरान भारत सरकार द्वारा वास्तविक विमुक्ति	राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई कुल राशि (प्रतिशत में)
(i) पीआरआई को अनुदान	1,385.00	653.50	653.50 (47)
(ए) परफोमेंस/ टाइड	831.00	392.10	392.10 (100)
(बी) अनटाइड अनुदान	554.00	261.40	261.40 (100)
(ii) यूएलबी को अनुदान	713.00	0.00	0.00
(ए) मिलियन प्लस शहर (परफोमेंस / टाइड अनुदान)	279.00	0.00	0.00
(बी) गैर-मिलियन प्लस शहर (60 प्रतिशत टाइड + 40 प्रतिशत अनटाइड अनुदान)	434.00	0.00	0.00
(iii) स्थानीय निकाय के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	492.10	464.22	130.24 (28)
स्थानीय निकायों के लिए कुल (i+ ii+iii)	2,590.10	1,117.72	783.74 (70)
राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ)	केन्द्रीय हिस्सा 526.00 राज्य का हिस्सा 175.00	1,027.20 0.00	465.79 (45)
राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)	केन्द्रीय हिस्सा 131.55 राज्य का हिस्सा 43.85	0.00 0.00	227.20 ¹ 75.60 ²
एसडीआरएफ के लिए कुल	876.40	1,027.20	768.59 ³ (75)

स्रोत: 15वीं वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

पीआरआई - पंचायती राज संस्थाएं और यूएलबी - शहरी स्थानीय निकाय

जैसा कि तालिका 1.11 से देखा जा सकता है, राज्य ने स्थानीय निकाय के तहत 'स्वास्थ्य क्षेत्र' और 'एसडीआरएफ' के लिए भारत सरकार से प्राप्त पूरी राशि को उचित निकायों / खातों में जारी नहीं किया, जिससे न केवल राज्य के लिए देनदारी पैदा हुई, बल्कि इच्छित योजनाओं / उद्देश्यों को भी प्रभावित किया गया।

राज्य को 2024-25 के दौरान मार्च 2024 के बाद पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि राज्यों को अनुदान केवल राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशों पर ही जारी किया जाना था। 2004 और 2024 के बीच चार एसएफसी का गठन किया गया था लेकिन कोई सिफारिश नहीं की गई थी। राज्य द्वारा फरवरी 2024 में 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, लेकिन 2024-25 के दौरान सिफारिशों को नहीं अपनाया गया था। इसके अलावा, पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण राज्य को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 2024-25 के दौरान भारत सरकार से अनुदान नहीं मिला क्योंकि यूएलबी केवल तभी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे जब

¹ 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रति वर्ष प्राप्त ₹ 113.60 करोड़ 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा जारी किए गए।

² राज्य हिस्से के रूप में 2020-21 और 2021-22 प्रति वर्ष के लिए ₹ 37.80 करोड़, 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा हस्तांतरित।

³ कुल में फुटनोट 1 और 2 में दिखाई गई राशि भी शामिल है।

विधिवत निर्वाचित निकाय स्थापित हो जाएं। चूंकि, राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए यूएलबी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे।

1.2.2 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों / वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम।

2020-21 से 2024-25 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों और उनके घटकों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.12 में दिखाई गई हैं।

तालिका 1.12: पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

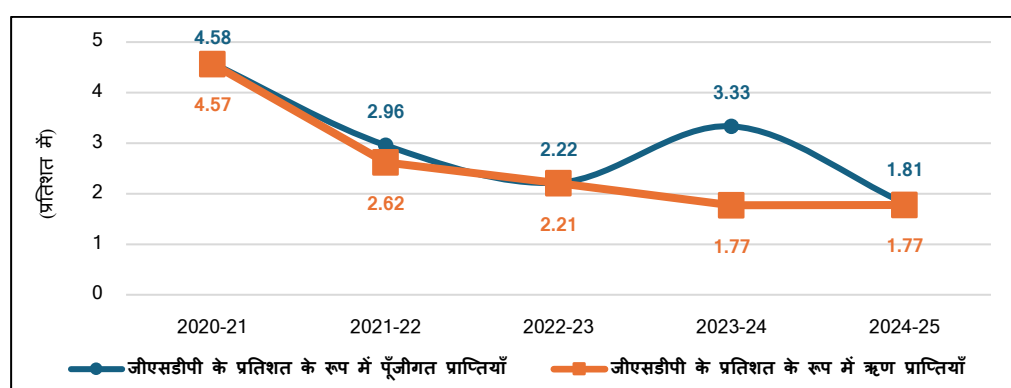
राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूँजीगत प्राप्तियाँ	13,595.36	11,131.60	9,188.71	15,523.83	9,357.31
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	48.78	1,291.73	46.41	7,276.70	196.69
लोक ऋणप्राप्तियाँ	13,546.58	9,839.87	9,142.30	8,247.13	9,160.62
आंतरिक ऋण	10,958.31	6,594.22	5,515.20	3,120.45	6,230.71
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	2,588.27	3,245.65	3,627.10	5,126.68	2,929.91
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
जीएसडीपी	(-) 4.40	26.79	10.15	12.39	10.87
पूँजीगत प्राप्तियाँ	41.00	(-) 18.12	(-) 17.45	68.94	(-)39.72
लोक ऋण प्राप्तियाँ	41.21	(-) 27.36	(-) 7.09	(-) 9.79	11.08
आंतरिक ऋण	19.54	(-) 39.82	(-) 16.36	(-) 43.42	99.67
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	507.60	25.40	11.75	41.34	(-)42.85

स्रोत: वित्त लेख

* अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध आंकड़ा सहित

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियाँ चार्ट 1.16 में दर्शाई गई हैं

चार्ट: 1.16 जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियाँ



राज्य की ऋण प्राप्तियाँ अधिक नहीं थीं, बल्कि यह देखा जा सकता है कि वे 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान घट रही थीं। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान इनमें ₹ 913.49 करोड़ की वृद्धि हुई है। जैसा कि चार्ट 1.16 से देखा जा सकता है, 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण प्राप्तियाँ ने कमी की प्रवृत्ति दिखाई।

राज्य डिस्कॉम द्वारा ऋणों और अग्रिमों की अप्रयुक्त शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण 2023-24 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक आँकड़े

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 15वें वित्त आयोग के अनुमानित राजस्व, घाटे और जीएसडीपी तथा वास्तविक आँकड़े तालिका 1.13 में दिए गए हैं।

तालिका 1.13: वास्तविकी के मुकाबले 15वें एफसी का अनुमान

(₹ करोड़ में)

	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला - वर्तमान मूल्य)	3,19,220	3,76,127	3,44,757	4,14,308	3,75,786	4,65,638	4,11,485	5,16,255
स्व-राजस्व प्राप्तियाँ	23,962	31,321	26,179	37,948	28,902	41,430	32,079	42,732
राज्य का स्व-कर राजस्व	15,041	21,290	16,472	25,118	18,235	28,005	20,297	28,501
राज्य का गैर-कर राजस्व	8,921	10,031	9,707	12,830	10,667	13,425	11,782	14,231
संघीय करों / शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी	21,780	27,735	24,228	31,405	27,262	37,352	30,972	42,557
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)	-2.20	-1.85	-2.70	-3.27	-3.30	-2.42	-3.80	-1.53
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	4.00	0.69	3.50	1.11	3.00	1.36	3.00	2.81

जैसा कि तालिका 1.13 से देखा जा सकता है, स्व-कर और गैर-कर प्राप्तियों सहित स्व-राजस्व प्राप्तियों के वास्तविक संग्रह में उपलब्धि, 15वें वित्त आयोग के अनुमानों से अधिक थी।

1.2.4 व्यय

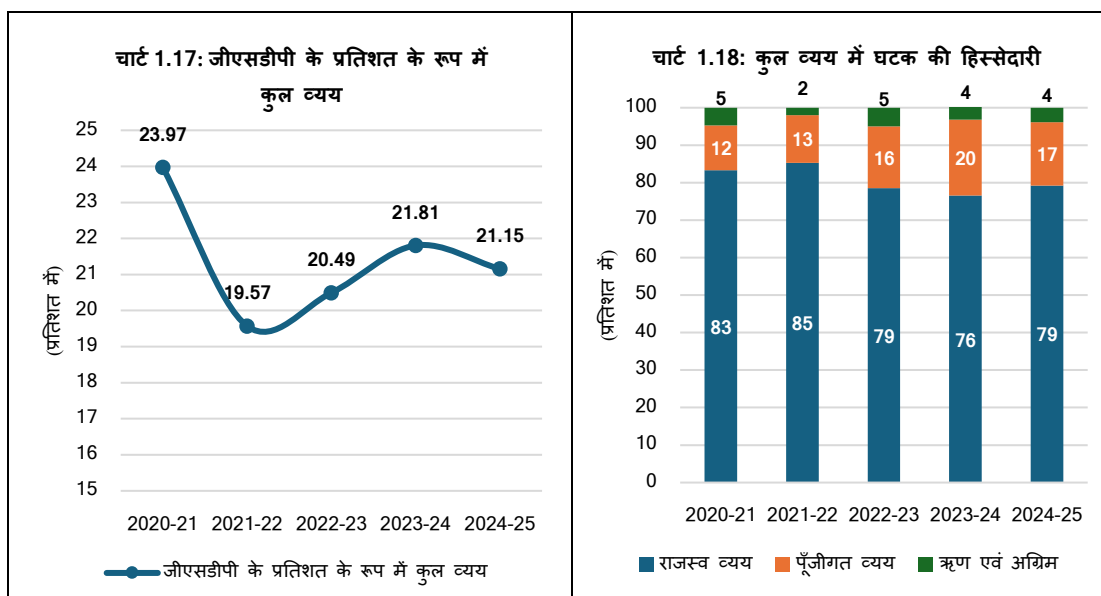
सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय में रखरखाव, मरम्मत और विभागों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए लागत शामिल हैं, जिसमें प्रशासनिक और स्थापना व्यय भी शामिल हैं। पूँजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण और परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या परिवर्धन से संबंधित है। ऋण और अग्रिम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि शामिल है, जो समय के साथ वसूल की जा सकती है। व्यय का विवरण, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों का हिस्सा क्रमशः तालिका 1.14, चार्ट 1.17 और चार्ट 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.14: कुल व्यय और उसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (कु. व्यय)	71,110	73,618	84,908	1,01,537	1,09,212
राजस्व व्यय (रा. व्यय)	59,264	62,778	66,681	76,676	86,565
पूँजीगत व्यय (पूँ. व्यय)	8,466	9,377	14,016	20,570	18,410
ऋण और अग्रिम	3,380	1,463	4,211	4,291	4,237

स्रोत: वित्त लेख



स्रोत: वित्त लेख

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए ₹ 1,09,212 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 653.50 करोड़ पीआरआई और यूएलबी के लिए वित्त आयोग से प्राप्त पास-थ्रू लेनदेन से संबंधित थे।

जैसा कि चार्ट 1.18 से देखा जा सकता है, कोविड के बाद के वर्षों (2022-23 और 2023-24) में पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी अधिक थी। यह ग्रामीण विकास और परिवहन क्षेत्रों के तहत बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर बढ़े हुए व्यय के कारण था। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में राजस्व व्यय का योगदान 2021-22 में 85.28 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 75.52 प्रतिशत हो गया। इसके बाद 2024-25 में पूँजीगत व्यय में गिरावट के कारण कुल व्यय में राजस्व व्यय की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई।

क्षेत्र-वार कुल व्यय

व्यय की क्षेत्र-वार संरचना तालिका 1.15 में दी गई है और कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी चार्ट 1.19 में दर्शायी गयी है।

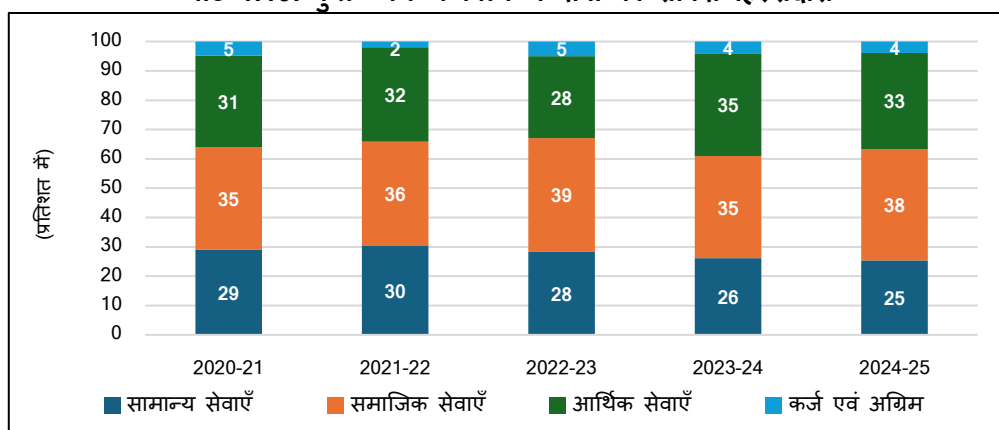
तालिका 1.15: क्षेत्र-वार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	20,674	22,290	24,134	26,559	27,749
सामाजिक सेवाएं	24,839	26,234	32,861	35,323	41,504
आर्थिक सेवाएं	22,217	23,631	23,702	35,364	35,722
स्थानीय निकायों को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण और अग्रिम	3,380	1,463	4,211	4,291	4,237
कुल व्यय	71,110	73,618	84,908	1,01,537	1,09,212

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी



स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 1.19 में दिखाया गया है, 2020-25 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं का कुल व्यय में एक बड़ा हिस्सा था, इसके बाद आर्थिक सेवाओं का था, जबकि सामान्य सेवाओं जैसे प्रशासनिक व्यय में कोविड के बाद के वर्षों में कमी आई।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में वृद्धि, कुल व्यय के अनुपात में इसकी वृद्धि, जीएसडीपी और राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 1.16 में दिखाई गई हैं।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय - बुनियादी मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (कु. व्यय)	71,110	73,618	84,908	1,01,537	1,09,212
राजस्व व्यय (रा. व्यय)	59,264	62,778	66,681	76,676	86,565
राजस्व प्राप्तियाँ (रा. प्राप्तियाँ)	56,150	69,722	80,245	87,929	94,489
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	105.55	90.04	83.10	87.20	91.61
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	83.34	85.28	78.53	75.52	79.26
राजस्व व्यय/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.98	16.69	16.09	16.47	16.77
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	4.97	5.93	6.22	14.99	12.90
जीएसडीपी वृद्धि	-4.40	26.79	10.15	12.39	10.87

स्रोत: वित्त लेखे

क. क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्र-वार संरचना तालिका 1.17 में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा चार्ट 1.20 में दर्शाया गया है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय परिशिष्ट 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.17: क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

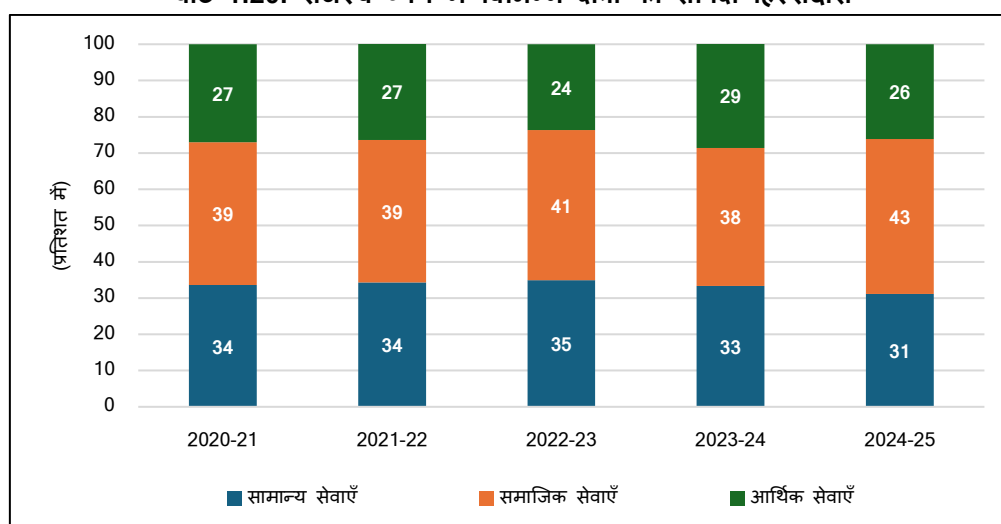
(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	19,903	21,556	23,261	25,590	26,979
सामाजिक सेवाएं	23,347	24,639	27,640	28,709	36,975
आर्थिक सेवाएं	16,014	16,583	15,781	22,377	22,611
सहायता-अनुदान और योगदान	0	0	0	0	0

स्रोत: वित्त लेख

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा व्यय हुआ जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा व्यय हुआ।

चार्ट 1.20: राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी



स्रोत: वित्त लेख

चूंकि झारखण्ड एक राजस्व अधिशेष राज्य है और 2024-25 के दौरान अल्प वृद्धि को छोड़कर कोविड के बाद के वर्षों में इसका राजस्व व्यय का कुल व्यय से अनुपात कम हो गया, जिसके कारण पूँजीगत व्यय के लिए अधिक राजकोषीय गुंजाइश थी। 2020-21 (कोविड वर्ष) को छोड़कर, 2020-25 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का जीएसडीपी से अनुपात 16 से 17 प्रतिशत के बीच रहा।

जैसा कि चार्ट 1.20 में दिखाया गया है, सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का अधिक हिस्सा था, जिसके बाद आर्थिक सेवाओं का था जो संकेत देता है कि राज्य ने विकास गतिविधियों जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹ 12,775 करोड़), सामाजिक कल्याण और पोषण (₹ 15,928 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 8,674 करोड़) और ऊर्जा (₹ 7,908 करोड़) पर अधिक व्यय किया।

ब. प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान; वेतन और मजदूरी पर व्यय; और पेंशन शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक तालिका 1.18 में दिया गया है और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अन्य व्यय के लिए शेष राजकोषीय गुंजाइश चार्ट 1.21 में दिया गया है।

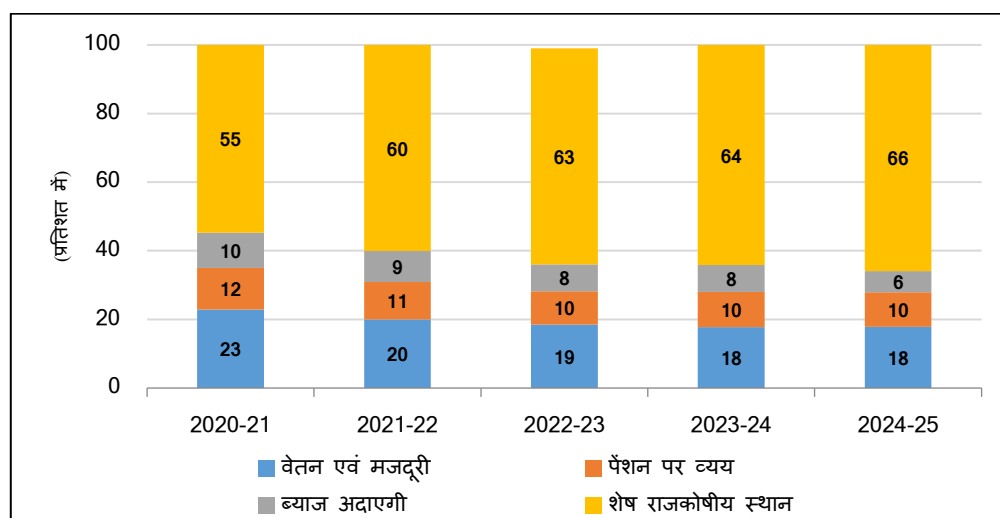
तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन और मजदूरी ⁴	12,837	13,929	14,852	15,634	16,849
पेंशन पर व्यय	6,797	7,614	7,803	9,014	9,522
ब्याज भुगतान	5,790	6,286	6,238	6,838	5,863
कुल	25,424	27,829	28,893	31,486	32,234
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	42.90	44.33	43.33	41.06	37.24

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और शेष राजकोषीय स्थान



स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 1.21 में दिखाया गया है, प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की संरचना दर्शाता है कि राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के प्रत्येक घटकों के योगदान में उतार-चढ़ाव के बावजूद, राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी 2021-22 से लगातार घट रही है, जिससे राज्य को अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक राजकोषीय स्थान मिल रहा है।

⁴ इसमें सहायता-अनुदान (वेतन) शामिल है: 2020-21 (₹ 2,872 करोड़); 2021-22 (₹ 2,915 करोड़); 2022-23 (₹ 3,253 करोड़); 2023-24 (₹ 3,600 करोड़) और 2024-25 (₹ 4,172 करोड़)।

स. सब्सिडी

वर्तमान वर्ष के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,058 करोड़ (63.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा सब्सिडी में ₹ 3,237 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी, तालिका 1.19 में दिखाई गई है।

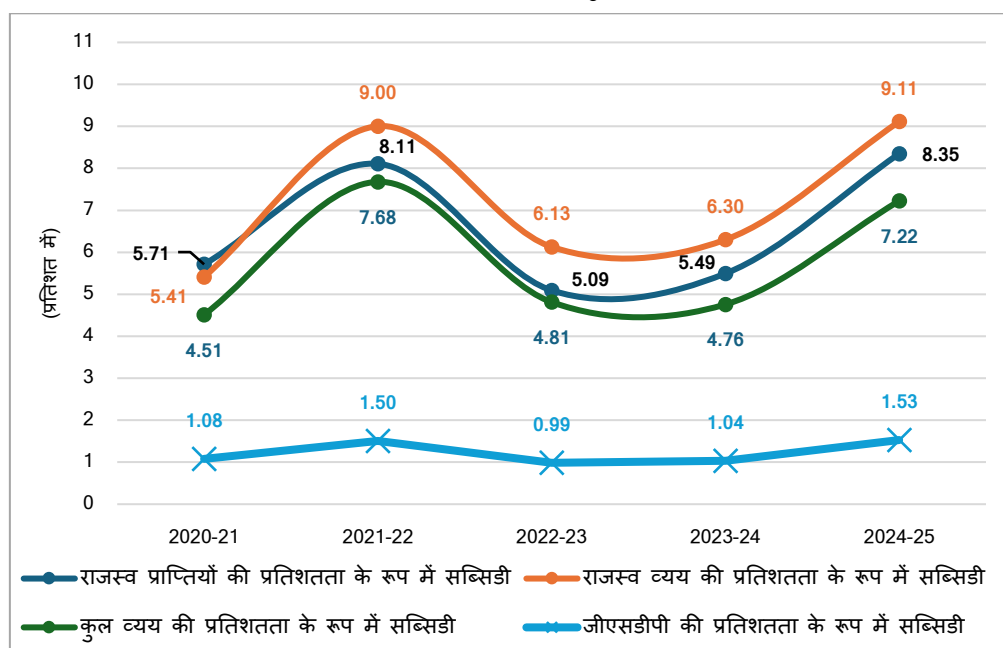
तालिका 1.19: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	फसल व कृषिकर्म	876	2,025	754	615	877
2	ऊर्जा	1,000	2,072	1,890	2,300	5,537
3	सार्वजनिक वितरण	1,243	1,318	1,367	1,689	1,233
4	डेयरी विकास	36	51	35	87	101
5	पशुपालन	40	30	39	133	124
6	अन्य विभाग	13	157	2	7	17
कुल सब्सिडी		3,208	5,653	4,087	4,831	7,889

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख, झारखण्ड सरकार

चार्ट 1.22: सब्सिडी का प्रवृत्ति विश्लेषण

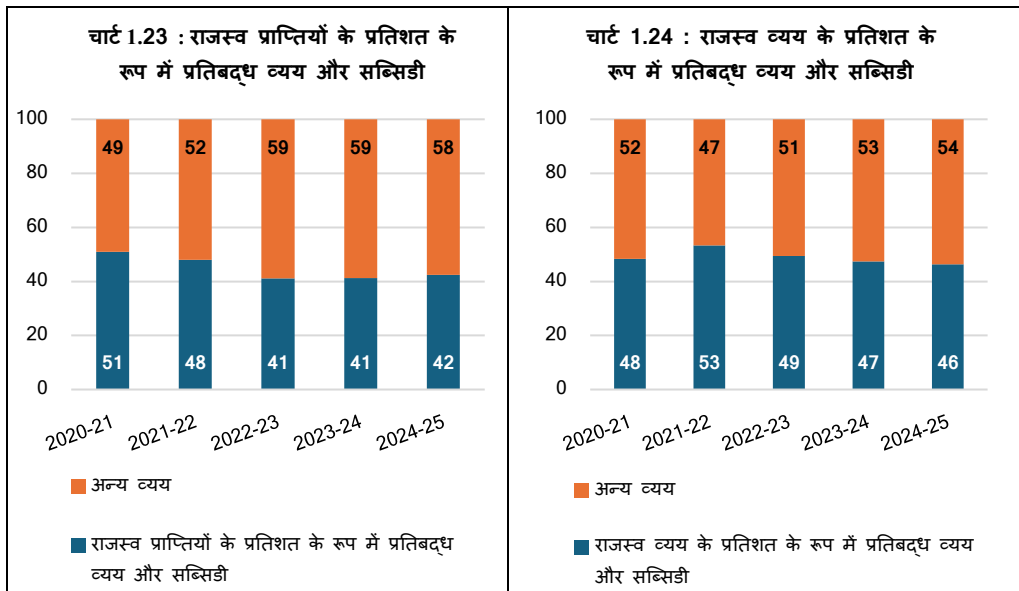


स्रोत: वित्त लेख

2024-25 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि राज्य सरकार ने अगस्त 2024 से प्रत्येक उपभोक्ता के लिए विद्युत की आपूर्ति बढ़ाकर 125 यूनिट से 200 यूनिट तक मुफ्त कर दी थी। 2024-25 के दौरान सब्सिडी में ₹ 3,058 करोड़ की वृद्धि के बावजूद, राज्य के पास वर्ष के दौरान ₹ 7,923.57 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, और जीएसडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहा।

प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी से वित्तीय तनाव

चार्ट 1.23 और चार्ट 1.24 क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी को एक साथ दर्शाते हैं।



2024-25 में, राज्य के ₹ 32,234 करोड़ के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन (₹ 16,849 करोड़), पेंशन (₹ 9,522 करोड़), और ब्याज भुगतान (₹ 5,863 करोड़) शामिल हैं, जो राजस्व प्राप्तियों का 34.11 प्रतिशत है। इसके अलावा, सब्सिडी ₹ 7,889 करोड़ थी, जिससे कुल अनम्य व्यय ₹ 40,123 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 42.46 प्रतिशत था। इस तरह के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय गुंजाइश को महत्वपूर्ण रूप से संकुचित करती है, जिससे राज्य की पूँजीगत निवेश और विकाशशील प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों का आवंटन करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाने और एक स्थायी राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के युक्तिकरण, बेहतर लक्षितकरण और वेतन एवं पेंशन प्रतिबद्धताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय में सुधार किया जाना चाहिए।

द. स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता तालिका 1.20 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थान	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
क. स्थानीय निकाय					
(i) नगर निगम और नगरपालिकाएँ	1,930.03	1,042.33	1,266.41	940.50	450.50
नगर निगमों और नगर पालिकाओं के पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	1,771.20	772.76	1,462.57	2,278.59	5,022.00
पीआरआई के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान	78.00	125.68	95.00	750.29	4,148.83
कुल (क) (i) + (ii)	3,701.23	1,815.09	2,728.98	3,219.09	5,472.50
ख. अन्य					
विश्वविद्यालय	1,771.17	1,807.60	2,393.67	2,423.63	2,410.61
विकास प्राधिकरण	8,283.26	8,751.59	8,033.52	7,154.86	5,888.96
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,119.77	2,469.66	1,000.70	2,867.77	3,274.61
अन्य संस्थाएँ	4,202.24	4,786.01	8,037.18	14,372.85	8,164.45
कुल (ख)	16,376.44	17,814.86	19,465.07	26,819.11	19,738.63
कुल (क+ख)	20,077.67	19,629.95	22,194.05	30,038.20	25,211.13
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कुल सहायता-अनुदान	4,207.24	125.68	95.00	750.29	4,148.83
राजस्व व्यय	59,264.00	62,778.00	66,681.00	76,676.00	86,565.00
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	33.88	31.27	33.28	39.18	29.12

स्रोत: वित्त लेख

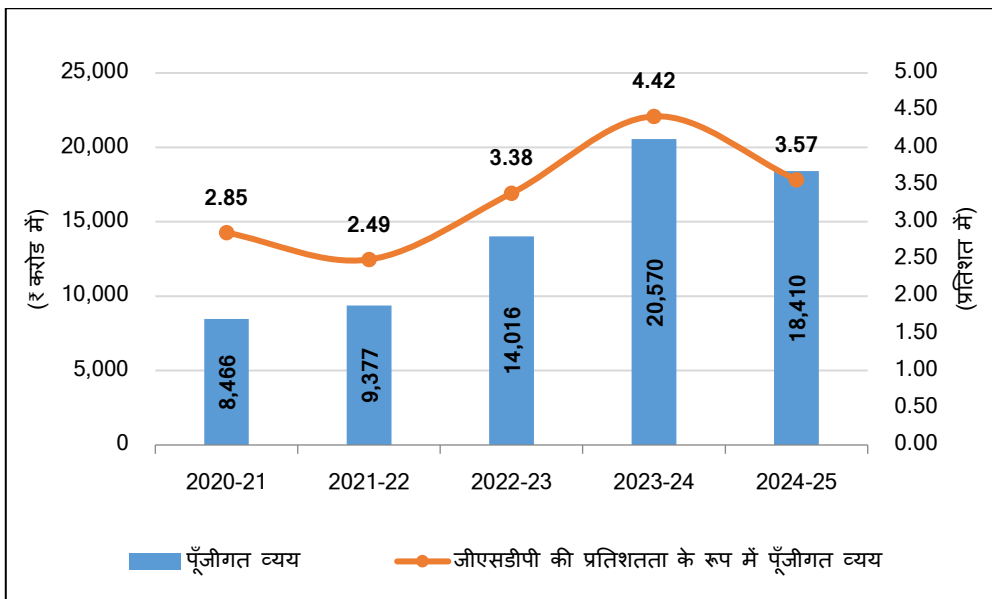
वर्तमान वर्ष के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,827.07 करोड़ (16.07 प्रतिशत) की कमी आई है। यह कमी मुख्य रूप से नगर निगमों और नगरपालिकाओं को सहायता में कमी (₹ 490.00 करोड़: 52.10 प्रतिशत) और अन्य संस्थानों (₹ 6,208.40 करोड़: 43.20 प्रतिशत) अर्थात् पेयजल और स्वच्छता के लिए सहायता-अनुदान (₹ 1,916.43 करोड़), विद्युत कंपनियाँ (₹ 5,658.57 करोड़) के कारण हुई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता की मात्रा पिछले वर्ष के 39.18 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष के दौरान 29.12 प्रतिशत रह गई।

हालांकि, पीआरआई के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता-अनुदान में ₹ 3,398.54 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना (₹ 3,482.14 करोड़) में अधिक धन प्रदान किए जाने के कारण हुई जो पिछले वर्ष अंबेडकर आवास योजना (₹ 100 करोड़) के लिए कम आवंटन से प्रतिपूरित हो गई थी।

1.2.4.2 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से निश्चित बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय है, जैसे कि सड़कें, इमारतें आदि/ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पूँजीगत व्यय बजटीय समर्थन और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/ ऑफ-बजट उधार से पूरा किया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/ निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों, अर्थात 2020-25 के दौरान राज्य में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां चार्ट 1.25 में दी गई हैं।

चार्ट 1.25: राज्य में पूँजीगत व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2021-22 से 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय से जीएसडीपी के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जो 2024-25 के दौरान घटने से पहले देखी गई।

2024-25 के दौरान ₹ 18,410 करोड़ के पूँजीगत व्यय के अलावा, राज्य सरकार ने पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 9,633 करोड़ भी हस्तांतरित किए, जिसमें स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दिए गए ₹ 4,148.83 करोड़ शामिल हैं।

क्षेत्र-वार पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय की क्षेत्र-वार संरचना तालिका 1.21 में दी गई है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय परिशिष्ट 1.3 में दिया गया है।

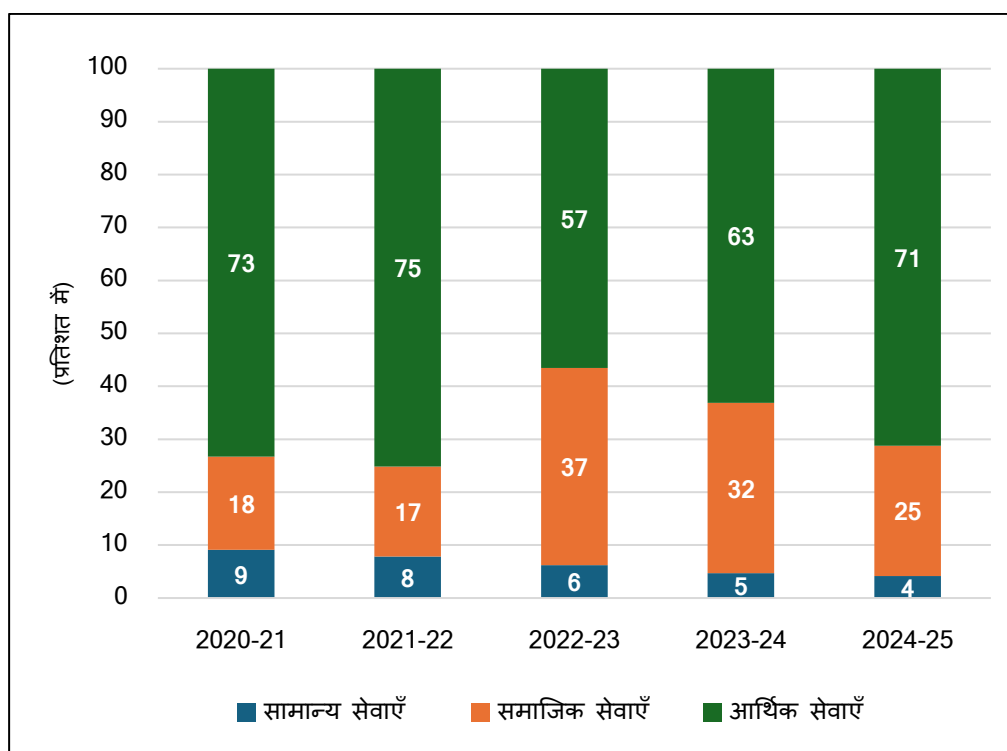
तालिका 1.21: क्षेत्र-वार पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	771	734	873	969	771
सामाजिक सेवाएं	1,492	1,595	5,221	6,614	4,529
आर्थिक सेवाएं	6,203	7,048	7,922	12,987	13,110

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.26: पूँजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष हिस्सेदारी



स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.24 और चार्ट 1.26 से देखा जा सकता है, आर्थिक सेवाओं ने पूँजीगत व्यय का प्रमुख हिस्सा प्राप्त किया, जिसमें सर्वाधिक व्यय ग्रामीण विकास (₹ 5,419 करोड़), परिवहन (₹ 5,211 करोड़) और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,759 करोड़) पर किया गया। 2024-25 के दौरान जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास (₹ 1,548 करोड़) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (₹ 250 करोड़) पर कम व्यय होने के कारण सामाजिक सेवाओं पर व्यय में काफी कमी आई।

अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरी पूँजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों में धन अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से राज्य वंचित रह जाता है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि से ऋण और ब्याज देयताओं की सेवा के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अपूर्ण परियोजनाओं (90 प्रतिशत तक की भौतिक स्थिति) का विवरण (वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर) तालिका 1.22 में दिखाया गया है।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 को अपूर्ण परियोजनाओं की आयु की रूपरेखा				31 मार्च 2025 को अपूर्ण परियोजना का विभाग-वार रूपरेखा		
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (व्यय)
2011-12	1	56.79	40.80	सड़क निर्माण	43	1,748.72 (942.35)
2013-14	1	12.19	7.66	ग्रामीण विकास	7	54.08 (33.73)
2016-17	2	113.60	72.14	ग्रामीण कार्य	74	812.35 (352.58)
2018-19	3	58.49	38.24	पेयजल एवं स्वच्छता	9	358.61 (264.65)
2019-20	7	598.48	333.59	भवन निर्माण	4	185.27 (57.98)
2020-21	11	501.16	320.95	जल संसाधन	18	720.19 (518.60)
2021-22	5	239.35	184.48			
2022-23	8	112.55	67.62			
2023-24	74	1,416.56	809.14			
2024-25	43	770.05	295.27			
कुल	155	3,879.22	2,169.89	कुल	155	3,879.22 (2,169.89)

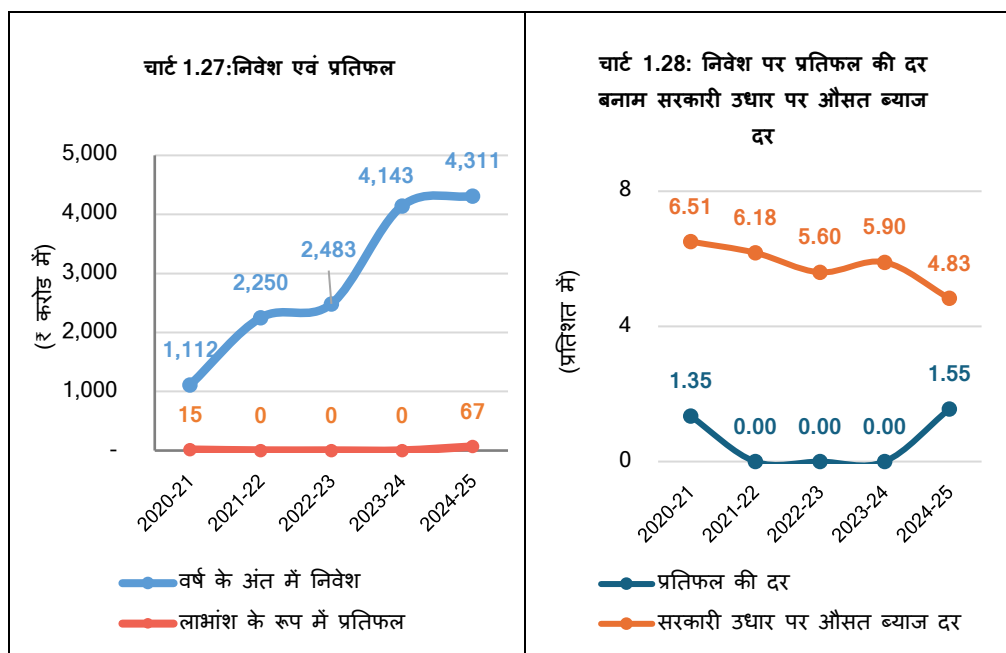
2024-25 तक ₹ 3,879.22 करोड़ की अनुमानित लागत में से इन 155 परियोजनाओं पर ₹ 2,169.89 करोड़ व्यय किए गए थे। इन 155 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 2,169.89 करोड़ का पूँजीगत व्यय अवरुद्ध रहा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लक्षित वर्ष से एक से 12 वर्ष के बीच विलंब हुआ।

वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX (सरकार की प्रतिबद्धताएं- अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची) में अपूर्ण जानकारी (राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त) के कारण, लेखापरीक्षा वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, लंबित भुगतान की स्थिति (भविष्य की देनदारी) और संशोधित लागत 31 मार्च 2025 तक, यदि कोई हो, का पता नहीं लगा सकी।

क. कंपनियों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, कंपनियों और अन्य निकायों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 4,311.37 करोड़ था, जिसमें 23 सरकारी कंपनियाँ (₹ 3,936.37 करोड़), 22 सहकारी समितियाँ (₹ 328.59 करोड़) और एक ग्रामीण बैंक (₹ 46.41 करोड़) शामिल हैं।

कंपनियों, निगमों और सहकारी बैंकों और समितियों में वर्ष के अंत में निवेश की प्रवृत्ति और इस निवेश पर प्रतिफल चार्ट 1.27 में दर्शाया गया है। सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर के मुकाबले निवेश पर प्रतिफल की दर को चार्ट 1.28 में दर्शाया गया है।



2024-25 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 66.93 करोड़ (1.55 प्रतिशत) था (शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक लागत के आधार पर)। 2020-25 के दौरान प्रतिफल शून्य और 1.55 प्रतिशत के बीच ही था। इसके अलावा, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 23 सरकारी कंपनियों में ₹ 3,936.37 करोड़ का निवेश किया गया था, जिनमें से केवल पांच⁵ कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 66.93 करोड़ का लाभांश दिया था।

लाभांश नीति की कमी और इसका प्रभाव

एक पूर्ण परिभाषित लाभांश नीति, लाभ कमाने वाले उद्यमों से न्यूनतम प्रतिफल की मांग करती है, राज्य सरकार को पीएसयू में निवेश से अपने प्रतिफल को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है और पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी को बढ़ाती है। यह देखा गया कि राज्य ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए लाभांश नीति तैयार नहीं की है या लागू नहीं की है।

राज्य में 32 पीएसयू हैं, जिनमें से 29 कार्यशील हैं और तीन गैर-कार्यशील हैं। 29 कार्यशील पीएसयू में से, दो⁶ पीएसयू ने 2024-25 के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। इन पीएसयू के वित्तीय विवरणों की जाँच से पता चला कि एक पीएसयू (झारखण्ड राज्य पुलिस आवास निगम लिमिटेड) का शुद्ध लाभ ₹ 9.75 करोड़ था और उसने वर्ष के दौरान ₹ 4.00 करोड़ का लाभांश दिया था।

⁵ (i) झारखण्ड राज्य पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड: ₹ 4.00 करोड़ (ii) झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम: ₹ 15.70 करोड़ (iii) झारखण्ड राज्य पेय निगम लिमिटेड: ₹ 20.00 करोड़ (iv) झारखण्ड अन्वेषण और खनन निगम लिमिटेड: ₹ 27.01 करोड़ (v) झारखण्ड चिकित्सा और स्वास्थ्य अवसंरचना विकास खरीद निगम लिमिटेड: ₹ 0.22 करोड़

⁶ झारखण्ड राज्य पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड और जेबीवीएनएल

डिस्कॉम के नुकसान का विश्लेषण

झारखण्ड में, एकमात्र डिस्कॉम (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) वर्षों से नुकसान उठा रहा है। 2020-21 से 2024-25 तक के नुकसान का विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है।

तालिका 1.23: 2020-25 के दौरान जेबीवीएनएल के हानि की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार वार्षिक हानि
2020-21	2,200.00
2021-22	2,088.38
2022-23	3,618.51
2023-24	2,620.56
2024-25	1,999.69

डिस्कॉम को नुकसान की भरपाई या उसे कम करने के लिए राज्य द्वारा कोई सब्सिडी सहायता नहीं दी गई थी। हालांकि, उपभोक्ता विपत्रों से समायोजन के अधीन उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला विद्युत प्रदान करने के लिए डिस्कॉम को सब्सिडी प्रदान की गई थी।

जाँच के दौरान यह देखा गया कि पीएसयू और अन्य से विद्युत खरीद के बकाया का भुगतान करने के लिए 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः ₹ 2,369.52 करोड़, ₹ 2,105.31 करोड़ और ₹ 1,407.60 करोड़ सरकार ने जेबीवीएनएल को ऋण प्रदान किया।

2015-16 के दौरान, राज्य ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बॉन्ड के तहत एकमुश्त उधार के रूप में ₹ 5,553.37 करोड़ प्रदान किए। उसके बाद उदय बॉन्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया।

यह भी देखा गया कि विपत्र माह सितंबर 2025 के अंत में, राज्य के 31 विभागों में विद्युत की उपभोग के एवज में ₹ 956.16 करोड़ का बकाया था। विद्युत विपत्रों के बड़े बकाया वाले विभागों को तालिका 1.24 में दिखाया गया है।

तालिका 1.24: 31.10.2025 को विद्युत विपत्रों के बड़े बकाए वाले विभाग

क्र.सं.	विभाग का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	शहरी विकास और आवास	423.23
2	पेयजल एवं स्वच्छता	261.95
3	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन	57.50
4	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	53.77
5	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास	50.87
6	ग्रामीण विकास (पंचायती राज प्रभाग)	21.88
7	कृषि, पशुपालन और सहकारिता	15.88
8	जल संसाधन	13.54

सरकारी विभागों के खिलाफ विद्युत विपत्रों के बड़े बकाए ने घाटे में चल रही डिस्कॉम पर वित्तीय तनाव को बढ़ा दिया।

इसके अलावा, राजस्व संग्रह बढ़ाने और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विपत्रों के विलंबित/गैर-भुगतान के जोखिम को कम करने के लिए, जेबीवीएनएल ने मौजूदा मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदलने की पहल की है। 18.70 लाख के लक्ष्य के मुकाबले, अक्टूबर 2025 तक केवल 10.17 लाख मीटर की प्रतिस्थापना की गई। इसी तरह, 1,37,693 वितरण ट्रांसफार्मरों में मीटर लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध, और ग्रामीण और शहरी फीडरों को फीडर-वार ऊर्जा लेखांकन को सक्षम करने के लिए, अक्टूबर 2025 तक केवल 21,667 मीटर स्थापित किए गए थे।

ख. राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, राज्य सरकार ने भी कई संस्थानों / संगठनों को ऋण और अग्रिम प्रदान किया है। तालिका 1.25 में 31 मार्च 2025 को ऋणों और अग्रिमों की स्थिति और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने उधारी पर ब्याज प्राप्तियों को ब्याज भुगतान के साथ साथ दर्शाया गया है।

तालिका 1.25: 2020-25 के दौरान संवितरित और वसूल किए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋण की प्रारंभिक शेष राशि	20,846.24	24,177.23	24,348.48	28,513.21	25,527.36
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	3,379.77	1,462.98	4,211.14	4,290.85	4,237.10
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	48.78	1,291.73	46.41	7,276.70	196.69
बकाया ऋणों की अंतिम शेष राशि	24,177.23	24,348.48	28,513.21	25,527.36	29,567.77
शुद्ध योग	3,330.99	171.25	4,164.73	-2,985.85	4,040.41
प्राप्त ब्याज	22.62	35.88	70.55	16.62	35.31
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर	0.11	0.16	0.29	0.06	0.13
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.51	6.18	5.60	5.90	4.83
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान की गई ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-)6.40	(-)6.02	(-)5.31	(-)5.84	(-)4.70

स्रोत: वित्त लेख

जैसा कि तालिका 1.25 से देखा जा सकता है, राज्य के संस्थानों के विरुद्ध ₹ 29,568 करोड़ की बड़ी राशि बकाया थी, जिसमें से ₹ 28,407 करोड़ की बड़ी राशि विद्युत कंपनियों के साथ बकाया थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया राशि के विरुद्ध वसूली की गई राशि बहुत कम थी, सिवाय वर्ष 2023-24 के, जब विद्युत कंपनियों द्वारा ₹ 7,231 करोड़ की अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई थी।

1.3 आकस्मिकता निधि

झारखण्ड सरकार का आकस्मिकता निधि राज्य विधानसभा द्वारा इसके प्राधिकरण के लंबित होने पर अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने के लिए

अभिप्रेत है। विधानसभा द्वारा अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दिए जाने के बाद निधि की वसूली की जाती है। निधि का कोष ₹ 500 करोड़ है।

2024-25 के दौरान विभिन्न बजटीय शीर्षों के तहत निधि से ₹ 635.96 करोड़ निकाले गए थे। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक कुल राशि की वसूली कर ली गई थी। 31 मार्च 2025 को, आकस्मिकता निधि ने ₹ 500 करोड़ की अपनी शेष राशि बरकरार रखी।

आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय का विवरण अध्याय-II के कंडिका 2.8 में चर्चा की गई है।

1.4 लोक लेखा

कुछ लेन-देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखे में घटक-वार शुद्ध शेष तालिका 1.26 में दिया गया है।

तालिका 1.26: लोक खाते में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	-1,194.40	-1,001.19	-1,016.98	-1,557.44	-2,238.21
रक्षित निधि	(ए) ब्याज सहित रक्षित निधि	-6,320.39	-5,904.48	-5,131.79	-7,995.66	-10,680.10
	(बी) ब्याज रहित रक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
जमा और अग्रिम	(ए) ब्याज सहित जमा राशि	-25.33	-24.15	-78.94	-79.27	-23.87
	(बी) ब्याज रहित जमा राशि	-24,331.45	-23,585.14	-26,876.14	-30,768.65	-31,536.41
	(सी) अग्रिम	19.67	19.67	17.66	0.00	4.23
उचंत और विविध	(बी) उचंत	-146.35	-119.25	-414.30	-382.43	-364.32
	(सी) अन्य खाते	2,855.90	4,519.46	5,187.74	8,151.32	53.47
	(डी) विदेशी सरकारों के साथ खाते	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ई) विविध	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
प्रेषण	(ए) मनी ऑर्डर, और अन्य प्रेषण	-133.68	-125.38	-87.35	-53.36	-227.05
	(बी) अंतर-सरकारी समायोजन खाता	7.23	12.74	10.81	5.27	2.67
कुल		-29,267.20	-26,206.12	-28,387.69	-32,678.62	-45,757.99

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: धनात्मक आँकड़े डेबिट शेष दर्शाते हैं और ऋणात्मक आँकड़े क्रेडिट शेष दर्शाते हैं।

2024-25 के दौरान ब्याज सहित रक्षित निधि और लघु बचत, भविष्य निधि में वृद्धि के कारण क्रेडिट शेष में वृद्धि हुई। मुख्य शीर्ष 8443-108-लोक निर्माण जमा और 8448-107-राज्य विद्युत बोर्ड कार्य निधि के तहत ब्याज रहित जमा ने भी क्रेडिट शेष में वृद्धि में योगदान दिया।

1.4.2 रक्षित निधि

राज्य सरकार के लोक लेखे के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए रक्षित निधि बनाई जाती है। ये निधि समेकित निधि या बाहरी अभिकरणों से प्राप्त अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती है। इसमें ब्याज सहित रक्षित निधि और ब्याज रहित रक्षित निधि शामिल हैं।

31 मार्च 2025 को तीन ब्याज सहित निधि और दो ब्याज रहित रक्षित निधि थे। 31 मार्च 2025 को इन रक्षित निधियों में बकाया शेष राशि तालिका 1.27 में दी गई है।

तालिका 1.27: प्रमुख रक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रक्षित निधि का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	ब्याज प्राप्ति	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष राशि
क	ब्याज सहित रक्षित निधि	8,395.67	3,012.18	0.00	327.75	11,080.10
1	राज्य आपदा मोचन कोष	3,034.96	1,368.80	0.00	52.88	4,350.88
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	5,209.31	1,491.98	0.00	274.87	6,426.42
3	राज्य आपदा शमन निधि	151.40	151.40	0.00	0.00	302.80
ख.	ब्याज रहित रक्षित निधि	2,270.95	1,324.41	49.92	0.00	3,645.28
1	हास निधि	1,570.87	592.00	0.00	0.00	2,162.87
2	अन्य निधि (पेंशन मोचन निधि)	700.08	732.41	49.92	0.00	1,482.41
	सकल योग	10,666.62	4,336.59	49.92	327.75	14,725.38

स्रोत: वित्त लेखे

रक्षित निधि के तहत ₹ 14,725.38 करोड़ के कुल अंत शेष में से, केवल ₹ 3,295.28 करोड़ का निवेश किया गया था और शेष राशि राज्य की देयताओं के रूप में बनी रही।

1.4.3 नकद शेष

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष (₹ 0.45 करोड़) बनाए रखना चाहिए। यदि शेष राशि इस न्यूनतम से कम हो जाती है, तो कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/विशेष निकासी सुविधा/ओवरड्राफ्ट जैसे उपकरणों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसकी अर्थोपाय अग्रिम सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को आरबीआई द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया था (17 अप्रैल 2020 से ₹ 1,152 करोड़, जो बाद में 31 मार्च 2022 से घटकर ₹ 1,067 करोड़ हो गया)। राज्य सरकार को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1,225.00 करोड़ थी (31 मार्च 2025 को)।

राज्य सरकार ने साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिए थे; हालांकि, वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने मार्च 2025 के महीने में तीन अलग-अलग मौकों पर ₹ 1,327.87 करोड़ की कुल राशि विशेष अर्थोपाय अग्रिम के रूप में ली है, लेकिन मार्च 2025 के महीने में तीन अलग-अलग मौकों पर ₹ 886.94 करोड़ की राशि चुकाई है, जिससे ₹ 440.93 करोड़ की शेष राशि बची है। हालांकि, वर्ष 2024-25 में अर्थोपाय अग्रिम पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया है।

राज्य सरकार अधिशेष नकद शेष के साथ-साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों और कोषागार विपत्रों में कर्णांकित रक्षित निधियों को निवेश करती है। इन निवेशों से होने वाली आय '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत जमा की जाती है।

2023-24 और 2024-25 के लिए नकद शेष और निवेश का विवरण तालिका 1.28 में दिए गए हैं।

तालिका 1.28: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	31 मार्च 2025 को अंत शेष राशि
क. सामान्य नकद शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	-86.66	-53.08
नकद शेष निवेश खाते में रखी गई निवेश	8,114.26	0.00
कुल (क)	8,027.60	-53.08
ख. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे वन और लोक निर्माण के पास नकद	36.90	53.31
आकस्मिक व्यय के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ स्थायी अग्रिम	0.16	0.16
कर्णांकित निधि का निवेश	2,670.95	3,295.28
कुल (ख)	2,708.01	3,348.75
कुल (क + ख)	10,735.61	3,295.67
ब्याज प्राप्त हुआ	97.12	101.19

स्रोत: वित्त लेखे

कर्णांकित निधि के तहत शेष राशि ₹ 14,725.39 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 3,295.28 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया था और ₹ 11,430.11 करोड़ का उपयोग सरकार द्वारा किया गया था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान निवेश खाते में नकद शेष का विवरण तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29: नकद शेष निवेश खाता (प्रमुख शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

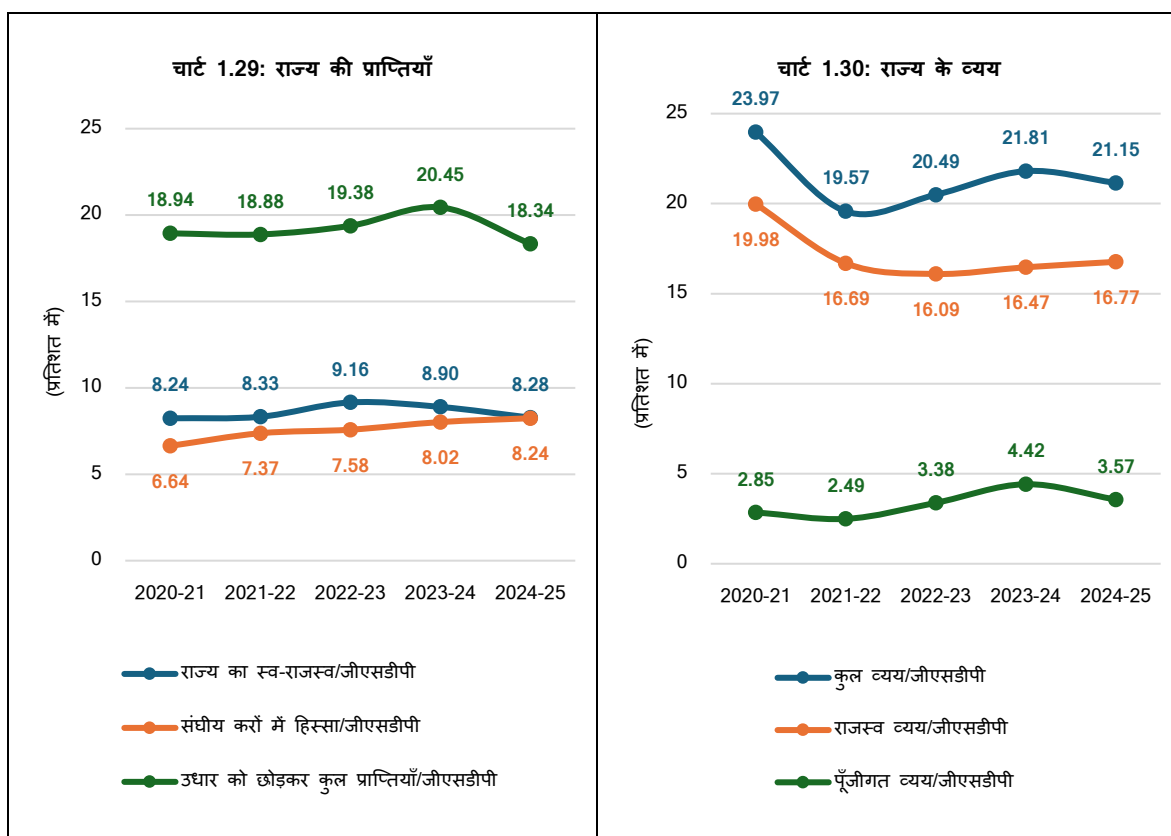
वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / कमी (-)	अर्जित ब्याज
2020-21	3,070.62	2,811.20	(-) 259.42	58.58
2021-22	2,811.20	4,480.63	1,669.43	58.63
2022-23	4,480.63	5,149.41	668.78	91.14
2023-24	5,149.41	8,114.26	2,964.85	97.12
2024-25	8,114.26	0.00	(-) 8,114.26	101.19

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.29 से देखा जा सकता है, 2024-25 के अंत में नकद शेष निवेश खाते का अंत शेष शून्य था। सरकार को वर्ष के दौरान ₹ 101.19 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।

1.5 राजकोषीय संधारणीयता

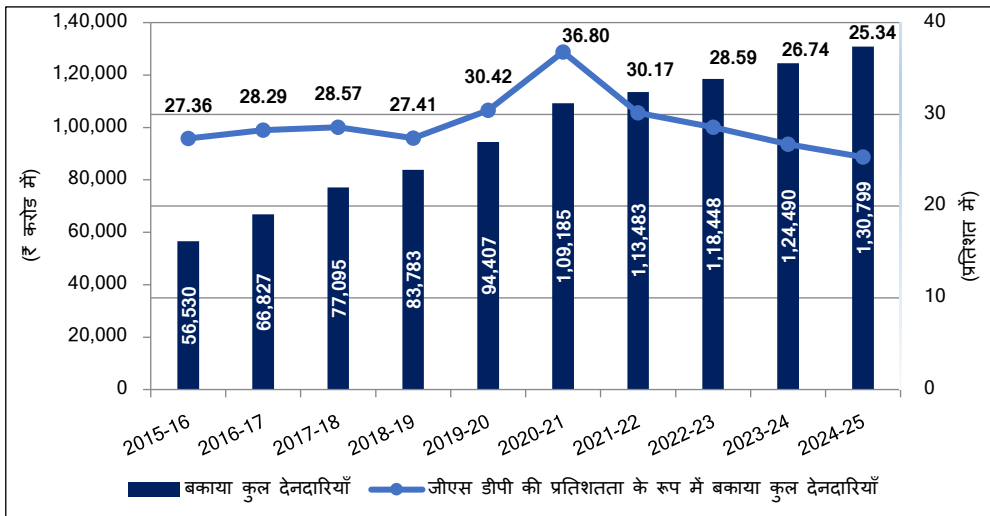
राजकोषीय संधारणीयता सरकार की अपनी आय और व्यय को इस तरह से प्रबंधित करने की क्षमता है कि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अत्यधिक उधार या अस्थिर ऋण संचय के बिना लोक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और ऋण पुनर्भुगतान जैसी अपनी वर्तमान और भविष्य की बाध्यताओं को पूरा कर सके। इसका तात्पर्य दीर्घकालिक रूप से राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है। चार्ट 1.29 और चार्ट 1.30 क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाता है।



1.5.1 लोक देयता प्रबंधन

वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक जीएसडीपी के लिए राज्य की बकाया देनदारियाँ और उनका प्रतिशत चार्ट 1.31 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.31: बकाया लोक देयता और जीएसडीपी में इसका प्रतिशत



स्रोत: वित्त लेख

जैसा कि चार्ट 1.31 से देखा जा सकता है, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया कुल देयता का अनुपात दस साल की अवधि के उत्तरार्ध में कमी की प्रवृत्ति को दर्शाता है जो राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत देता है।

1.5.1.1 देयताओं की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयताओं में आम तौर पर राज्य का आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम एवं लोक लेखा देनदारियां शामिल हैं। वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार देयता की प्रवृत्ति तालिका 1.30 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.30: घटक-वार देयता रुझान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया कुल देयता	1,09,184.99	1,13,482.47	1,18,448.22	1,24,490.00	1,30,798.56
लोक ऋण	76,938.35	82,531.53	84,944.37	83,688.98	85,169.98
आंतरिक ऋण	71,956.90	74,538.31	73,580.43	70,658.82	69,595.32
भारत सरकार से ऋण*	4,981.45	7,993.22	11,363.94	13,030.16	15,574.66
लोक लेखा देनदारियां	32,246.24	30,950.94	33,503.85	40,801.02	45,628.58
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1,194.40	1,001.19	1,016.98	1,557.44	2,238.20
ब्याज सहित रक्षित निधि	6,720.39	6,340.46	5,531.78	8,395.66	11,080.09
ब्याज रहित रक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
ब्याज सहित जमा राशि	25.33	24.15	78.94	79.27	23.87
ब्याज रहित जमा राशि	24,306.12	23,585.14	26,876.15	30,768.65	31,536.42
कुल बकाया देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.65	3.94	4.38	5.10	5.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	296,664	376,127	414,308	465,638	516,255
कुल बकाया देयता / जीएसडीपी (प्रतिशत)	36.80	30.17	28.59	26.74	25.34
उधार और अन्य देनदारियां					
कुल प्राप्तियाँ	32,562.62	25,623.42	31,856.35	44,607.36	41,329.08

राजकोषीय देयता के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल पुनर्भुगतान	17,784.23	21,325.90	26,890.62	35,447.09	35,020.51
ब्याज भुगतान के बिना उपलब्ध शुद्ध धन	14,778.39	4,297.52	4,965.73	9,160.27	6,308.57
पुनर्भुगतान / प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	54.62	83.23	84.41	79.46	84.74

स्रोत: वित्त लेखे

* वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, भारत सरकार से ऋण में क्रमशः ₹ 1,689 करोड़ और ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

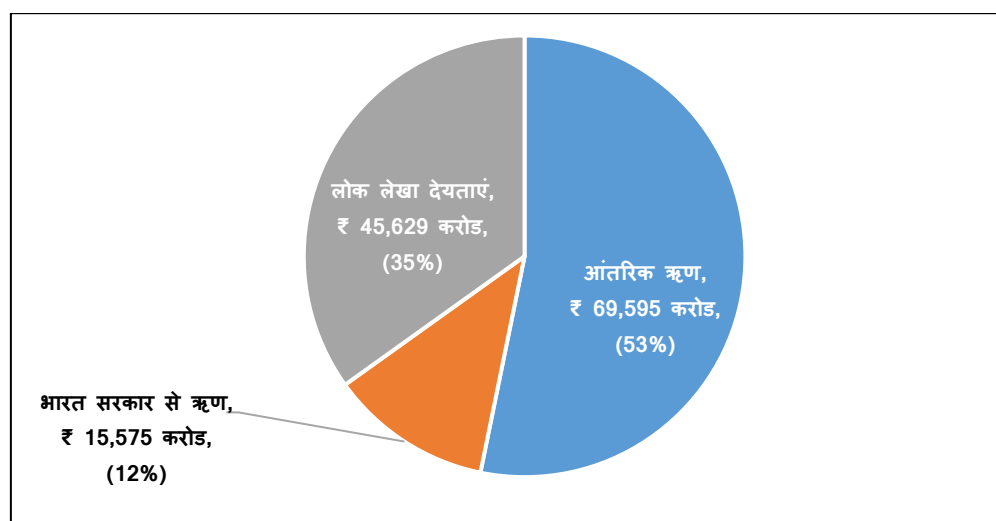
जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से 2020-21 और 2021-22 के दौरान बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,173.41 करोड़ से, ₹ 3,118.51 करोड़ को प्रोफार्मा सुधार करके भारत सरकार के ऋण के शेष राशि से समायोजित किया गया था। 2023-24 और 2024-25 के दौरान बकाया देयताओं में ₹ 1,054.90 करोड़ की राशि शामिल थी।

तालिका 1.30 से देखा जा सकता है कि राज्य का आंतरिक ऋण 2022-23 से लगातार कम हुआ है। 2020-21 से 2024-25 के दौरान जीएसटी मुआवजे⁷ में कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण (₹ 4,173.41 करोड़) और पूँजीगत निर्माण⁸ के लिए विशेष सहायता (₹ 10,263.25 करोड़) के कारण भारत सरकार से ऋण में वृद्धि हुई।

जीएसडीपी से कुल देयताओं का अनुपात 2020-21 में 36.80 प्रतिशत से लगातार घटकर 2024-25 में 25.34 प्रतिशत हो गया।

2024-25 के अंत में कुल देयताओं का ब्यौरा चार्ट 1.32 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.32: 2024-25 के अंत में कुल देयताओं का विभाजन



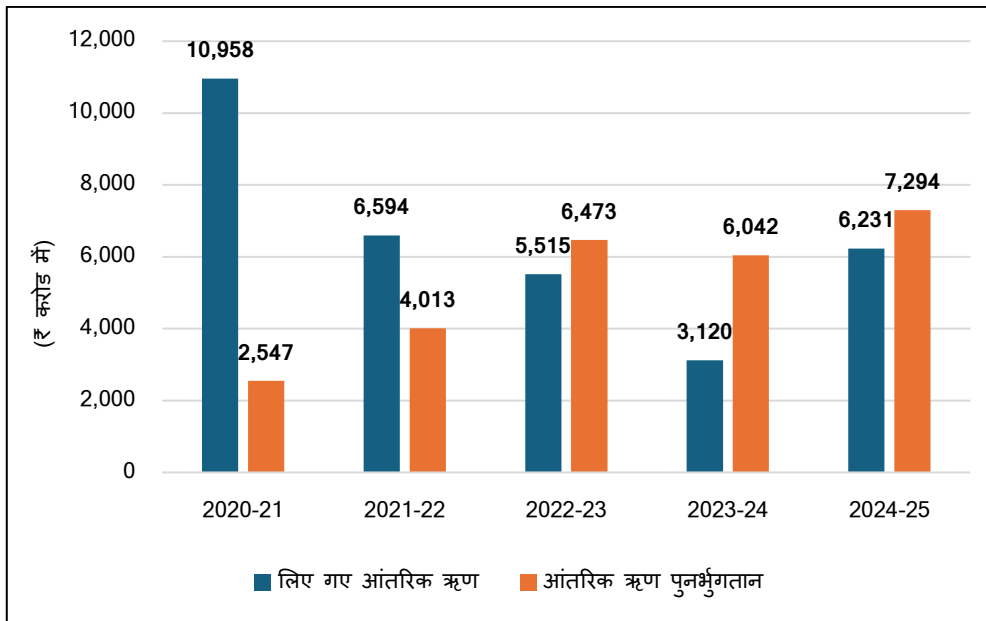
स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.33 पांच वर्षों की अवधि यानी 2020-25 के दौरान पुनर्भुगतान के मुकाबले राज्य की आंतरिक ऋण प्राप्तियों की मात्रा को दर्शाता है।

⁷ 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़।

⁸ 2022-23 में ₹ 2,964.32 करोड़, 2023-24 में ₹ 4,580.61 करोड़ और 2024-25 में ₹ 2,718.32 करोड़।

चार्ट 1.33: पुनर्भुगतान के मुकाबले आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ



स्रोत: वित्त खाते

जैसा कि चार्ट 1.33 से देखा जा सकता है, राज्य की आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ 2021-22 से 2024-25 के दौरान ₹ 3,120 करोड़ और ₹ 6,594 करोड़ के बीच रही। 2023-24 में, बाजार ऋणों (₹ 1,000 करोड़) के तहत उधार कम था, जबकि 2020-21 में यह काफी अधिक (₹ 10,958 करोड़) था, जो कोविड के कारण राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए था।

विभाजन के लगभग 25 वर्ष बाद भी मार्च 2025 तक बिहार राज्य की वित्तीय देयताओं का विभाजन उत्तराधिकारी राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

1.5.1.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजीगत निर्माण और विकाशशील गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। तालिका 1.31 में 2020-25 के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग और प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.31: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	कुल उधार*	13,546.58	9,839.87	9,142.30	8,247.13	9,160.62
2.	पूर्व के उधार (मूलधन) का पुनर्भुगतान	2,744.82	4,247.08	6,729.46	6,384.02	7,679.63
3.	निवल पूँजीगत व्यय	8,465.66	9,376.90	14,015.59	20,569.69	18,409.97
4.	निवल ऋण और अग्रिम	3,330.99	17.25	4,164.73	-2,985.85	-4,040.39

क्र.सं.	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
5.	राजस्व व्यय का हिस्सा निवल उपलब्ध उधार से पूरा किया जाता है	इन वर्षों के दौरान राजस्व अधिशेष को देखते हुए, उधार ली गई धनराशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया गया था।				

स्रोत: वित्त लेखे

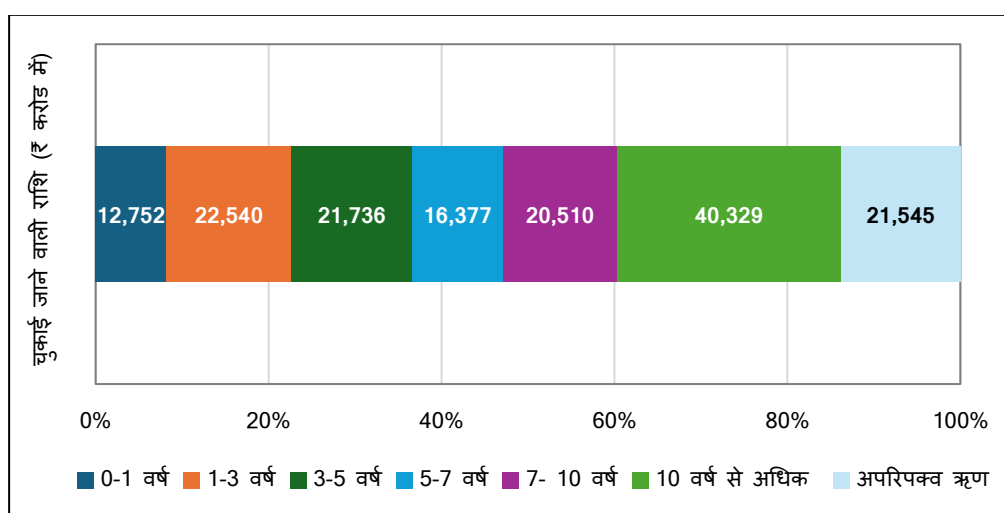
* जिसमें 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,689 करोड़ में और ₹ 2,484.41 करोड़ में शामिल हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

राज्य को 2024-25 के दौरान पहले की उधारियों के एवज में ₹ 7,679.63 करोड़ का भुगतान करना था, जिसे वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष से पूरा किया गया था।

1.5.1.3 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल चार्ट 1.34 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.34: लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल



स्रोत: वित्त लेखे

* 2020-22 के दौरान जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,173.41 करोड़ को छोड़कर।

टिप्पणी: पिछले पांच वर्षों में राज्य द्वारा भुगतान की गई औसत ब्याज दर के आधार पर ऋण पुनर्भुगतान की गणना की गई है।

जैसा कि चार्ट 1.34 से देखा जा सकता है, राज्य को अगले 10 वर्षों में ₹ 93,915 करोड़ की राशि चुकानी होगी। हालाँकि, राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आलोक में मूलधन और ब्याज का भुगतान संधारणीय होगा, लेकिन नए उधार लेने की स्थिति में यह बदल सकता है।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप

2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप को तालिका 1.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.32: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1 राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-)	-3,114	6,944	13,564	11,252	7,924
2 निवल पूँजीगत व्यय	-8,466	9,377	14,016	20,570	18,410
3 निवल ऋण और अग्रिम	-3,331	171	4,165	-2,986	4,040
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न					
1 बाजार उधार	8,900	3,746	400	-1,950	-1,450
2 भारत सरकार से ऋण	2,390	3,012	3,372	4,785	2,544
3 एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-769	-770	-769	-769	-769
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	281	-395	-588	-202	1,156
5 लघु बचत, पीएफ, आदि	-23	-193	16	540	681
6 जमा और अग्रिम	3,215	-722	3,346	3,910	708
7 उचंत और विविध	53	-27	295	-32	-18
8 प्रेषण	44	-14	-36	-28	176
9 रक्षित निधि	1,076	-180	-309	4,131	4,059
10 कुल घाटा	15,167	4,457	5,727	10,385	7,087
11 नकद शेष में वृद्धि / कमी	-256	-1,853	-1,110	-4,053	7,440
12 सकल राजकोषीय घाटा	14,911	2,604	4,617	6,332	14,527

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.32 से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा (₹ 14,527 करोड़) पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि और राज्य द्वारा ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के कारण हुआ। ₹ 14,527 करोड़ के राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण (₹ 2,544 करोड़) और रक्षित निधि (₹ 4,059 करोड़) द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के पश्चात घाटा संकेतक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 7,923.57 करोड़ (जीएसडीपी का 1.53 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹ 14,526.81 करोड़ (जीएसडीपी का 2.81 प्रतिशत) जबकि प्राथमिक घाटा ₹ 8,663.80 करोड़ (जीएसडीपी का 1.68 प्रतिशत) था। हालांकि, 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने राजस्व प्रकृति के सहायता-अनुदान की राशि ₹ 2,879.71 करोड़ को पूँजीगत व्यय के तहत दर्ज की थी। जैसा कि, अध्याय-II के कंडिका 2.5.6 में चर्चा के अनुसार, ₹ 42.45 करोड़ की राशि को पूँजीगत खंड के बजाय राजस्व खंड के तहत दर्ज किया गया था।

इसके अलावा, यह देखा गया कि ₹ 314.10 करोड़ (एसडीआरएफ का ब्याज: ₹ 262.75 करोड़, सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का ब्याज: ₹ 5.31 करोड़ और ह्रास निधि में अल्प हस्तांतरण: ₹ 46.04 करोड़ में) उनके निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित नहीं किए गए थे।

ब्याज का गैर-हस्तांतरण, निर्दिष्ट निधियों में अल्प हस्तांतरण और कुल ₹ 314.10 करोड़ के व्यय के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष में

अतियुक्ति हुई। इसलिए, लेखापरीक्षा के बाद राजस्व अधिशेष ₹ 4,772.21 करोड़ (जीएसडीपी का 0.92 प्रतिशत) रहा। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के बाद राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹ 14,526.81 करोड़ और ₹ 8,663.80 करोड़ के स्थान पर क्रमशः ₹ 14,840.91 करोड़ और ₹ 8,977.90 करोड़ होगा।

1.5.3 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

2007 के एफआरबीएम अधिनियम और इसके संशोधनों के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्य सरकार का लक्ष्य है:

- राजस्व घाटे को समाप्त करना एवं इसके उपलब्धि को पूरा करने पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति के साथ राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के अंदर बनाए रखना।
- बकाया ऋण-जीएसडीपी का अनुपात 25 प्रतिशत से कम रखा जाना है।
- ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 18 से 25 प्रतिशत तक सीमित रखना, और
- वेतन पर व्यय राज्य की स्व-राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- झारखण्ड एक मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) का भी पालन करता है और उसे आकस्मिक देयताओं और लिए गए ऑफ-बजट उधार को प्रकट करने की आवश्यकता है।

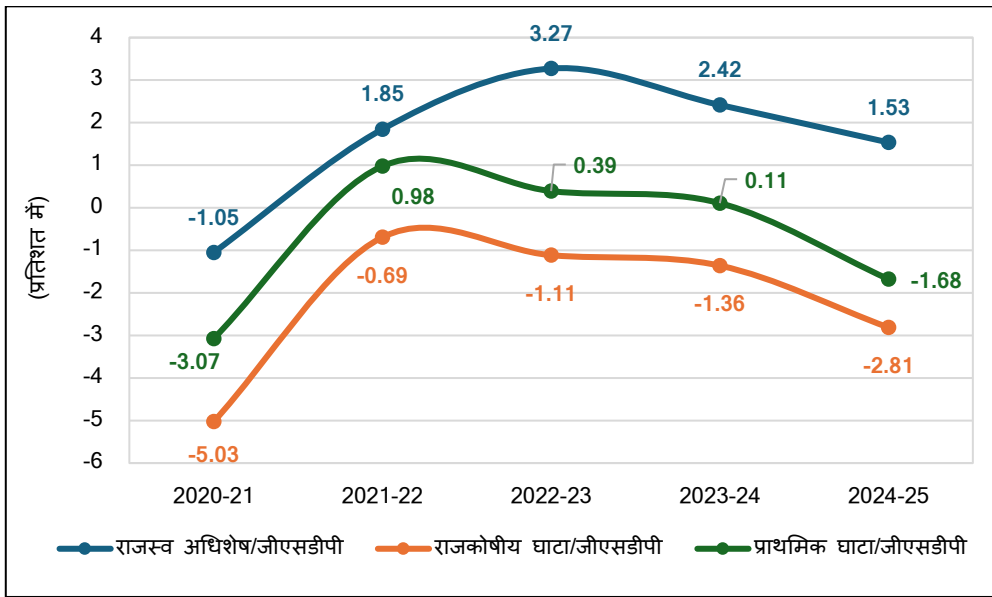
वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियां तालिका 1.33 में विस्तृत हैं।

तालिका 1.33: राज्य एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

वित्तीय मानदंड		एफआरबीएम के तहत तैयार एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	राजस्व घाटे को शून्य तक कम करना।				
	उपलब्धि	-3,114	6,944	13,564	11,252	7,924
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	-5.00	-4.00	-3.50	-3.00	-3.00
	उपलब्धि	-5.03	-0.69	-1.11	-1.36	-2.81
जीएसडीपी के कुल बकाया देनदारी का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	27.00	33.00	33.15	30.60	27.00
	उपलब्धि	36.23	29.06	27.58	26.51	25.13
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति का 18 से 25 प्रतिशत				
	उपलब्धि	10.31	9.02	7.77	7.78	6.20

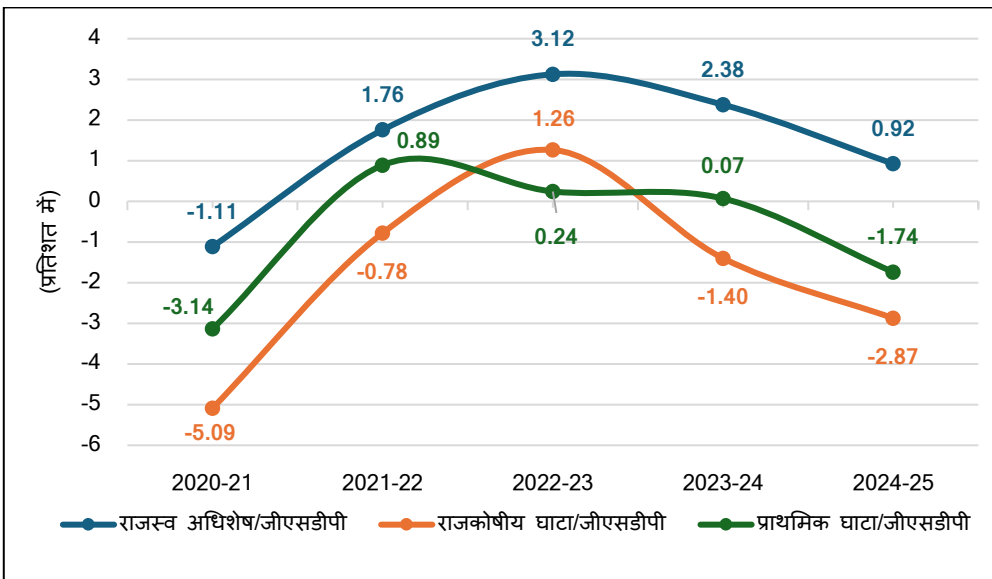
जैसा कि तालिका 1.33 से देखा जा सकता है, 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, जीएसडीपी से बकाया देनदारी का अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान की उपलब्धि एफआरबीएम लक्ष्यों के भीतर थे, सिवाय 2020-21 (कोविड वर्ष)।

चार्ट 1.35: घाटे का प्रवृत्ति विश्लेषण

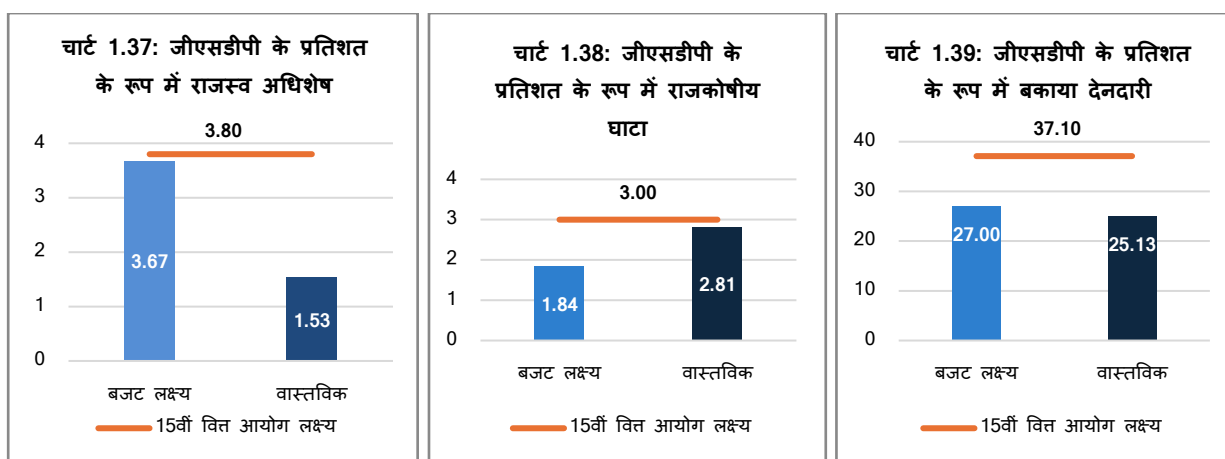


ब्याज के गैर-हस्तांतरण, निर्दिष्ट निधियों में अल्प हस्तांतरण और व्यय के गलत वर्गीकरण पर विचार करते हुए, लेखापरीक्षा के पश्चात जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटा परिवर्तित होगा, जैसा कि चार्ट 1.36 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.36: लेखापरीक्षा के बाद घाटे का रुझान विश्लेषण



15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में उपलब्धियों के संबंध में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य चार्ट 1.37, चार्ट 1.38 और चार्ट 1.39 में दिए गए हैं।



स्रोत: वित्त लेख और बजट दस्तावेज

2020-21 को छोड़कर, राज्य के पास 2020-25 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष था। 2020-21 को छोड़कर 2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्य से कम रहा। जीएसडीपी से बकाया देयता का अनुपात झारखण्ड एफआरबीएम अधिनियम के तहत एमटीएफपी में निर्धारित मापदंडों का वर्ष 2020-21 के दौरान उल्लंघन हुआ, शेष अवधि के लिए लक्ष्य के भीतर था।

1.5.4 ऋण संधारणीयता विश्लेषण

ऋण संधारणीयता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण संधारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 1.34 में दिया गया है।

तालिका 1.34: ऋण संधारणीयता संकेतकों में रुझान

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	ऋण संधारणीयता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	समग्र देनदारियां या समग्र ऋण	1,07,495.99	1,09,309.06	1,14,274.81	1,23,435.09	1,29,743.66
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.86	1.69	4.54	8.02	5.11
3	जीएसडीपी (नाममात्र रूप से)	2,96,664.00	3,76,126.69	4,14,308.00	4,65,638.00	5,16,255.00
4	नाममात्र जीडीएसपी वृद्धि (प्रतिशत)	-4.40	26.79	10.15	12.39	10.87
5	कुल ऋण / जीएसडीपी (प्रतिशत)	36.23	29.06	27.58	26.51	25.13
6	सकल उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	72.40	107.76	103.99	94.80	98.92
7	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	27.60	-7.76	-3.99	5.20	1.08
8	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	5,790.48	6,286.05	6,238.29	6,838.95	5,863.01
9	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	7.41	7.48	7.38	8.12	6.85
10	राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	10.31	9.02	7.77	7.78	6.20
11	राजस्व घाटा / अधिशेष	-3,113.86	6,943.94	13,563.59	11,252.08	7,923.57
12	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	2,676.62	13,229.99	19,801.88	18,091.03	13,786.58
13	प्राथमिक शेष (पीबी)	-9,119.52	3,682.05	1,621.29	507.19	-8,663.80
14	प्राथमिक शेष / जीएसडीपी (प्रतिशत)	-3.07	0.98	0.39	0.11	-1.68
15	समग्र ऋण पर निवेश पर प्रतिफल ^६ और प्रभावी ब्याज दर के बीच अंतर	-7.31	-7.33	-7.11	-8.06	-6.48

क्र.सं.	ऋण संधारणीयता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
16	चलनिधि प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधनों का उपयोग) (कई अवसरों में)	शून्य	16.00	शून्य	शून्य	3.00
17	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार + प्राथमिक शेष)	-18,909.64	20,131.87	3,948.57	4,121.54	-5,176.22
18	डोमर गैप					
क	जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर)	2,19,483.31	2,45,855.59	2,63,531.00	2,83,284.00	3,03,178.00
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर)	-5.30	12.02	7.19	7.50	7.02
ग	सीपीआई (प्रतिशत) पर आधारित मुद्रास्फीति	5.32	4.51	6.14	5.73	3.77
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.41	7.48	7.38	8.12	6.85
च	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	2.09	2.97	1.24	2.39	3.08
छ	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि - वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-7.39	9.05	5.95	5.11	3.95
ज	प्राथमिक शेष (पीबी)	-9,119.52	3,682.05	1,621.29	507.19	-8,663.80

स्रोत: वित्त लेखे

*6003-'आंतरिक ऋण' और 6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम' शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि का योग लोक ऋण राशि है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1,689 करोड़ में और ₹ 2,484.41 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में भारत सरकार से प्राप्त के बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं।

\$ प्रभावी ब्याज दर प्राप्तियों द्वारा मापे गए निवेश पर पतिफल

निवेश पर प्रतिफल(आरओआई) = ब्याज प्राप्तियाँ / वितरित ऋणों और अग्रिमों के प्रारम्भिक और अंतिम स्टॉक का औसत *100

** भुगतान की गई ब्याज / (लोक ऋण का आरंभिक शेष + लोक ऋण का अंत शेष/ 2) (प्रतिशत में)

राज्य सरकार के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

गिरते ऋण-जीएसडीपी अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। इसके अलावा, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति में बताया गया है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहने की प्रवृत्ति होगी या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक होता है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ रहा होगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में अंततः गिरावट होगी। **तालिका 1.34** से देखा जा सकता है कि:

- राज्य का ऋण भार जीएसडीपी से कुल देयता के अनुपात द्वारा मापा जाता है। महामारी से उबरने के परिणामस्वरूप, राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार शुरू हुआ, जिससे महामारी के बाद के वर्षों में राज्य के ऋण बोझ में लगातार सुधार हुआ और ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2020-21 में 36.23 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 25.13 प्रतिशत हो गया। कोविड के बाद के वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेतों को देखते हुए, राज्य लगातार राजस्व अधिशेष हासिल करने में सक्षम रहा है।
- नाममात्र वृद्धि के विपरीत, प्रभावी ब्याज दर मुख्य रूप से मुद्रास्फीति द्वारा संचालित थी जो आरबीआई द्वारा निर्धारित महामारी के बाद की अवधि (2021-25) में उच्च सहनशीलता दायरे (लगभग 4-6 प्रतिशत) में मंडरा रही थी, जो यह

दर्शाता है कि मुद्रास्फीति ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को कम रखने में मदद की ताकि वास्तविक रूप में ब्याज अंतर में वृद्धि (जीआईडी) अनुकूल रहे।

- जीआईडी के योगदान और राज्य के ऋण भार में परिवर्तन पर प्राथमिक शेष को विघटित करने से पता चलता है कि प्रतिकूल जीआईडी और नकारात्मक प्राथमिक शेष दोनों ने 2020-21 में समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात के वृद्धि में योगदान दिया, जिससे 2021-22 के बाद से समग्र देनदारी-जीएसडीपी अनुपात में लगातार गिरावट में अनुकूल हो गया।
- डोमार मानदंड से दर्शाता है कि 2020-21 में उधार की लागत को पूरा करने के लिए वृद्धि पर्याप्त नहीं थी, जिससे जीआईडी प्रतिकूल हो गया। हालाँकि, आर्थिक सुधार के संकेतों के बाद, 2021-22 में राज्य ने आधारभूत प्रभाव के कारण 12.02 प्रतिशत की पाँच वर्ष की उच्च वास्तविक वृद्धि देखी, जिससे 9.05 प्रतिशत पर अनुकूल जीआईडी हुआ। 2024-25 तक जीआईडी अनुकूल रहा जबकि 2024-25 में प्राथमिक शेष नकारात्मक ₹ 8,663.80 करोड़ हो गया।
- राज्य का ऋण भार समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात द्वारा मापा जाता है, यदि महामारी वर्ष 2020-21 को उपेक्षित कर दिया जाए तो, राज्य के एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रहा। राज्य 2020-25 के दौरान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण भार के भीतर अपने ऋण भार को बनाए रखने में भी सफल रहा।
- ब्याज भुगतान - राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में गिरावट और निवेश पर प्रतिफल तथा कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के बीच का अंतर, वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत देता है।

1.5.5 गारंटी की स्थिति - आकस्मिक देनदारियाँ

गारंटी उधारकर्ता के चूक करने की स्थिति में समेकित निधि पर आकस्मिक देनदारियाँ हैं। राज्य सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं आदि जैसी संस्थाओं द्वारा जुटाए गए ऋणों के लिए गारंटी देता है। पिछले पांच वर्षों के लिए प्रतिभूति और कुल प्राप्तियों के लिए बकाया प्रतिभूति का विवरण तालिका 1.35 में दिया गया है।

तालिका 1.35: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वर्ष के आरंभ में प्रतिभूतियों की बकाया राशि	607.15	607.15	607.15	4,998.38	4,998.38
वर्ष के अंत में बकाया प्रतिभूतियाँ	607.15	607.15	4,998.38	4,998.38	2,823.38

स्रोत: वित्त लेख और वार्षिक वित्तीय विवरण

31 मार्च 2025 तक ₹ 2,823.38 करोड़ की बकाया गारंटी ऊर्जा (₹ 2,535.38 करोड़) और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 288 करोड़) के संबंध में थी। हालाँकि, 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई थी।

राज्य ने प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन नहीं किया था और झारखण्ड एफआरबीएम अधिनियम, 2007 में राज्य द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूतियों की राशि के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (25 नवंबर 2025) कि प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और इसे उचित समय पर लागू किया जाएगा।

वर्ष 2024-25 की शुरुआत में ₹ 4,998.38 करोड़ की बकाया प्रतिभूति से वर्ष के दौरान राज्य के खातों से ₹ 2,175 करोड़ की प्रतिभूति हटा दी गई, जिससे ₹ 2,823.38 करोड़ की शेष राशि बच गई।

1.5.6 राजकोषीय गुंजाइश पर अमुक्त देनदारियाँ

यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अप्रत्याशित देनदारियाँ भविष्य के विकासशील और बुनियादी ढांचे के व्यय के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश को कम कर देंगी। पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी पैदा करने के अलावा, यह राज्य की स्थायी तरीके से संसाधन जुटाने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होती है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने वर्षों से कई अविमुक्त देनदारियाँ जमा कर ली हैं, जिनका राजकोषीय संधारणीयता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसमें शामिल हैं:

- समेकित हास निधि (सीएसएफ) में ₹ 46.04 करोड़ का अल्प योगदान।
- ₹ 268.06 करोड़ की कुल अप्रतिदेय ब्याज देनदारियाँ (कंडिका 3.2.1)।

इन अविमुक्त देयताओं का संचयी मूल्य ₹ 314.10 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के लिए जीएसडीपी का 0.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का 2.16 प्रतिशत है।

1.6 निष्कर्ष

राज्य ने झारखण्ड एफआरबीएम अधिनियम में दिए गए समयसीमा से बहुत पहले अपने राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 2020-21 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व अधिशेष प्राप्त किया। 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम लक्ष्यों के अंदर था, सिवाय वर्ष 2020-21 के, जब यह लक्ष्य से थोड़ा अधिक था।

2022-23 के बाद राज्य के स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता ने कमी की प्रवृत्ति दिखाई। 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संबंध में उत्प्लावकता 0.77 प्रतिशत अंक कम हो गया।

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय 2020-21 में 45 प्रतिशत से लगातार घटकर 2024-25 में 34 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों के

प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2022-23 के बाद से बढ़ रही थी। 2024-25 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 8.35 प्रतिशत था।

राज्य की कुल देनदारियां 2023-24 में ₹ 1,23,435 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,29,744 करोड़ हो गईं। जीएसडीपी से वित्तीय देयताओं का अनुपात 27.00 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 25.13 प्रतिशत था। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की वित्तीय देयताओं का विभाजन अभी तक नहीं किया गया है।

1.7 अच्छी प्रथाएं

- राज्य सरकार ने ऋणों के परिशोधन के लिए स्थापित समेकित हास निधि में 2024-25 तक ₹ 2,162.87 करोड़ हस्तांतरित किए।
- एक पेंशन मोचन निधि की स्थापना की गई है, और पुरानी पेंशन योजना में बदलाव करने के कारण उत्पन्न होने वाली भविष्य की वित्तीय देयताओं को पूरा करने के लिए 2024-25 तक ₹ 1,482.41 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।

1.8 अनुशंसाएँ

- कर अनुपालन में सुधार करके तथा एक स्पष्ट गैर-कर राजस्व नीति लागू करके, विशेष रूप से लाभांश, खनन और ब्याज प्राप्तियों के लिए, और समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क और शुल्क को संशोधित करके राजस्व प्राप्ति को मजबूत किया जा सकता है।
- राजस्व व्यय और प्रतिबद्ध देयताओं को युक्तिसंगत बनाएं और विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाईश बनाने के लिए सब्सिडी का बेहतर तरीके से लक्षित करें।
- वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लाभांश नीति तैयार करके और राज्य द्वारा अपनी संस्थाओं और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों की निगरानी बढ़ाकर सार्वजनिक निवेश पर प्रतिफल में सुधार करें।
- केंद्र प्रायोजित योजना निधि को एसएनए स्पर्श खातों में समेकित और समय पर हस्तांतरित करके वित्तीय पारदर्शिता और बेहतर निधि प्रबंधन सुनिश्चित करें।